

ज्वाला एक्सप्रेस न्यूज



आर.एन.आई. नं. :- CHHHIN/2021/82386

सत्वी खबर सबसे पहले

online- jwalaexpress.com

वर्ष - 05, अंक -17

दुर्ग (छ.ग.), दिनांक 25 दिसंबर 2025 (प्रत्येक गुरुवार)

पृष्ठ - 8, मूल्य - 05 रुपए

देश और प्रदेश में खेलों को लेकर बहुत ही उत्साहजनक वातावरण

छत्तीसगढ़ में खेलों का विकास हमारी प्राथमिकता- मुख्यमंत्री साय



मुख्यमंत्री ने जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का किया शुभारंभ

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज यहां राजधानी रायपुर के कोटा रोड स्थित स्वामी विवेकानंद एथेलेटिक स्टेडियम में आयोजित 45वीं एनटीपीसी जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता के शुभारंभ किया। उन्होंने 45वीं एनटीपीसी जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए अपनी

शुभकामनाएं दी और खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उनका उत्साहवर्धन किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ का यह सौभाग्य है कि प्रदेश को राष्ट्रीय ट्राइबल गेम्स के आयोजन का अवसर मिला है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खेलो इंडिया के माध्यम से देश की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के बहुत अच्छे अवसर मिल रहे हैं। साथ ही आज पूरे देश और प्रदेश में खेल को लेकर बेहतर वातारण तैयार हो रहा है। उन्होंने

कहा कि छत्तीसगढ़ में खेलों का विकास हमारी प्राथमिकता में शामिल है। सरकार द्वारा सभी खेलों के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा को निखारने सभी सुविधाएं और प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी खेलो इंडिया के नये परिसरों की शुरुआत की गई है, इससे खेल प्रतिभाओं को सभी जरूरी सुविधाएं मिल रही हैं। राज्य में खेल अलंकरण समारोह का आयोजन किया जाता है

जिससे खिलाड़ियों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाता है। हमारी सरकार ओलंपिक में शामिल होने वाले एथलीट को 21 लाख रुपये देगी। यदि हमारे प्रदेश का कोई युवा खिलाड़ी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतता है तो उसे 3 करोड़, रजत पदक जीतने पर 2 करोड़ तथा कांस्य पदक जीतने वालों को एक करोड़ रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

उल्लेखनीय है कि 45वीं एनटीपीसी जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन छत्तीसगढ़ प्रदेश आरवरी एसोसिएशन एवं छत्तीसगढ़ खेल एवं युवा कल्याण विभाग के तत्वावधान में किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता 22 से 30 दिसंबर तक आयोजित होगी। प्रतियोगिता में 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगभग 500 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव श्री विक्रम सिसोदिया, छत्तीसगढ़ प्रदेश आर्चरी एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री कैलाश मोरारका, महासचिव श्री आयुष मोरारका, श्री ईश्वर प्रसाद अग्रवाल सहित विभिन्न प्रदेशों से आए खिलाड़ी, कोच,मैनेजर तथा गणमान्यजन व खेलप्रेमी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

‘जो कहा, वह किया, और जो नहीं कहा, वह भी करके दिखाया’ : केंद्रीय मंत्री नड्डा



रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार के सप्ता दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जांजगीर-चांपा जिले के खोखराभाठा पुलिस लाइन मैदान में आयोजित जनादेश परब में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने मंच से प्रदेश की उपलब्धियों, जनकल्याण और भविष्य की दिशा पर स्पष्ट संदेश दिया। वंदे मातरम और राज्यगीत के साथ आरंभ हुए कार्यक्रम में जनविश्वास, गौरव और निर्माण के संकल्प को दोहराया गया। केंद्रीय मंत्री श्री नड्डा ने कहा कि जो कहा था, वह किया – और जो नहीं कहा था, वह भी करके दिखाया। उन्होंने दो वर्षों के रिपोर्ट-कार्ड को रेखांकित करते हुए बताया कि सरकार ने किसानों, महिलाओं, युवाओं और श्रमिकों के हित में संवेदनशील और परिणामकारी निर्णय लिए हैं, जिनका असर जमीनी स्तर पर दिख रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के पहले महीने में किसानों को 3700 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान और बीते दो वर्षों में 1.25 लाख करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष अंतरण अन्नदाताओं के सम्मान का प्रमाण है। भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए 5 लाख से अधिक हितग्राहियों को 10-10 हजार रुपये की सहायता दी गई, जिससे उनकी सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा मजबूत हुई। केंद्रीय मंत्री श्री नड्डा ने कहा कि युवाओं के लिए पारदर्शी भर्ती तंत्र, 32 हजार पदों पर भर्ती की प्रक्रिया, लोक सेवा आयोग में पारदर्शिता, नालंदा लाइब्रेरी की स्थापना और आईटीआई के आधुनिकीकरण जैसे कदमों को उन्होंने ऋभविष्य-निर्माण की नींव ऋ बताया। महिलाओं के स्वावलंबन हेतु महतारी वंदन योजना और महतारी सदन, पीएम जनमन के तहत 70 लाख परिवारों को लाभ तथा धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण को उन्होंने सरकार की संवेदनशीलता का उदाहरण बताया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ का रेलवे बजट 22 गुना बढ़ा है, 32 अमृत स्टेशन वर्ल्ड-क्लास मानकों पर विकसित हो रहे हैं और आयुष्मान भारत, उज्ज्वला, जल जीवन मिशन, पीएम-किसान जैसी योजनाओं का व्यापक लाभ आमजन तक पहुंचा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने पर बधाई देते हुए कहा कि सरकार आम जनता के विश्वास पर खरा उतरने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

खेतों में अब सिर्फधान नहीं, खुशबू भी उग रही है : छत्तीसगढ़ में पुष्प खेती से बदल रही किसानों की तकदीर

राज्य में 12 हजार हेक्टेयर में फूल की खेती : दो साल में बढ़ा 3405 हेक्टेयर रकबा

रायपुर। छत्तीसगढ़ के खेतों में अब धान की फसल के साथ-साथ खुशबू और रंग भी लहलहाने लगे हैं। परंपरागत खेती से आगे बढ़ते हुए प्रदेश के किसान तेजी से पुष्प खेती की ओर रुख कर रहे हैं। बीते दो वर्षों में राज्य में फूलों की खेती का रकबा 3405 हेक्टेयर बढ़ा है और उत्पादन 35 हजार 866 मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। यह बदलाव न सिर्फखेती के स्वरूप को बदल रहा है, बल्कि किसानों की आमदनी में भी नई खुशहाली घोल रहा है।

राज्य सरकार की फसल विविधिकरण नीति के तहत वर्तमान में पुष्प फसलों का कुल रकबा 12 हजार हेक्टेयर हो चुका है। किसान अब ग्लोडियोस, रजनीगंधा और गेंदा जैसे फूलों की खेती कर रहे हैं, जिन्हें बाजार आसानी से मिल जाता है। मांग स्थिर होने के कारण फूल किसानों के लिए नगदी फसल बनते जा रहे हैं।



केंद्र परिवर्तित राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत पुष्प क्षेत्र विस्तार के लिए प्रति हेक्टेयर 50 हजार से 2.50 लाख रुपए की इकाई लागत पर 40 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान है, यानि किसानों को 20 हजार से एक लाख रुपए तक की सहायता सीधे मिल रही है।

उद्यानिकी विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्लोडियोस और रजनीगंधा फूल की अधिकतम दो हेक्टेयर में खेती पर अनुदान की पत्रता का प्रावधान है, जो कि 2.5 लाख की इकाई लागत पर एक लाख रुपए है। राज्य में इस वर्ष 125 हेक्टेयर में ग्लोडियोस तथा 50 हेक्टेयर में रजनीगंधा



पुष्प की खेती का लक्ष्य रखा गया है। गेंदा फूल की खेती के लिए इस वर्ष 1200 हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित है। इसकी खेती करने पर 50 हजार की लागत पर 20 हजार रुपए अनुदान का प्रावधान है। इस तरह राज्य में कुल 1375 हेक्टेयर क्षेत्र में पुष्प खेती के लिए सहायता देने का लक्ष्य रखा गया है।

राज्य में संरक्षित खेती के तहत

पॉलीहाउस और शेडनेट में एंथुरियम, ऑर्किड, कार्नेशन, जरबेरा, गुलाब, क्राइसैंथमम और लीलियम जैसे उच्च मूल्य वाले फूलों की खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। एंथुरियम और ऑर्किड के लिए 4000 वर्गमीटर तक 1000 रुपए प्रति वर्गमीटर की लागत पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। इसी तरह गुलाब, क्राइसैंथमम और लीलियम पर 45 रुपए प्रति वर्गमीटर की लागत पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि पुष्प खेती किसानों की आय बढ़ाने और युवाओं को कृषि से जोड़ने का प्रभावी माध्यम है। सरकार अनुदान, तकनीक और बाजार की व्यवस्था कर किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ फूलों की खेती का बड़ा केंद्र बनेगा। पुष्प खेती अब किसानों के लिए स्थायी आय का मजबूत साधन बन रही है। सरकारी प्रोत्साहन, बाजार की मांग और नई तकनीक के सहारे छत्तीसगढ़ के खेतों में फूलों की यह खुशबू दूर-दूर तक फैलने लगी है।

बस्तर संभाग में महिलाएं डेयरी व्यवसाय से बन रही हैं आत्मनिर्भर

रायपुर। रोजगार और स्वरोजगार के माध्यम से लोगों की आमदनी बढ़ाने के लिए बस्तर संभाग में डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा दिया जा रहा है। एनडीडीबी के माध्यम से कांकेर और कोण्डगांव जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत संचालित की जा रही। इस योजना में जनजातीय महिलाओं को डेयरी व्यवसाय से जोड़ा जा रहा है। गौरतलब है कि इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय 01 जून 2025 को कोण्डगांव जिले के भोंगापाल गांव से इस योजना शुभारंभ किया था।

बस्तर संभाग के कोण्डगांव एवं कांकेर जिले के 125 हितग्राहियों को ऋा एवं अनुदान पर दुधारू पशु प्रदाय के लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 47 महिलाओं के आवेदन पत्र बैंक से ऋा स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से 24 महिलाओं को 36 दुधारू पशु वितरित किया गया है। हितग्राहियों को अच्छे नस्ल की दुधारू गाय प्रदान करने हेतु एनडीडीबी डेयरी सर्विसेस द्वारा साहीवाल नस्ल की गाय (8-10 लीटर दूध प्रतिदिन उत्पादन क्षमता) राजस्थान एवं पंजाब क्षेत्र से चिन्हित कर अनुसूचित जनजाति महिलाओं को वितरण किया जा रहा है। दुग्ध महासंघ द्वारा वर्तमान में बस्तर संभाग अंतर्गत 95 कार्यशील दुग्ध समितियों के 4006 दुग्ध प्रदायकों के माध्यम से 15060 लीटर दूध प्रतिदिन संकलित किया जाकर, लगभग 8000 लीटर दूध प्रतिदिन कांकेर, कोण्डगांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर जिलों में विपणन किया जा रहा है। बस्तर संभाग में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए आगामी 5 वर्षों में 400 नयें ग्रामों को दुग्ध समिति के माध्यम से जोड़ा जायेगा। जिसमें लगभग 9000 दूध प्रदायक जुड़ेंगे एवं 48 हजार लीटर दूध संकलन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 28 हजार लीटर क्षमता के दुग्ध शीतलीकरण केन्द्रों एवं एक 1 लाख लीटर क्षमता का नवीन दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना बस्तर जिले में किया जायेगा।

किसानों की सुविधाओं और मंडी अधोसंरचना को मिलेगा नया आयाम : कृषि मंत्री राम विचार नेताम



पटेलपाली कृषि उपज मंडी में 6.15 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का भूमिपूजन

रायपुर। राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर रायगढ़ जिले में कृषि एवं मंडी अधोसंरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई। कृषि मंत्री एवं रायगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री श्री राम विचार नेताम ने आज कृषि उपज मंडी समिति पटेलपाली रायगढ़ में 6.15 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से प्रस्तावित विभिन्न विकास कार्यों का विधिवत पूजा-अर्चना के साथ भूमिपूजन किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी सहित जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य

नागरिक और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री श्री राम विचार नेताम ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों के कल्याण और कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रदेशभर में जनादेश परब का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विकास कार्यों को जनता के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी के अंतर्गत की गई घोषणाओं को ईमानदारी से धरातल पर उतारा जा रहा है। आज जिन कार्यों का भूमिपूजन

किया गया है, उनसे किसानों को बेहतर भंडारण सुविधा, सुगम आवागमन और आधुनिक मंडी अधोसंरचना उपलब्ध होगी, जिससे कृषि उपज के प्रबंधन और विपणन में उल्लेखनीय सुधार आएगा। इन कार्यों के पूर्ण होने से मंडी क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुदृढ़ होगी, किसानों को उपज के भंडारण एवं विक्रय में सुविधा मिलेगी तथा क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास को गति प्राप्त होगी।

वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने कहा कि प्रदेश में सरकार के गठन के बाद से रायगढ़ जिले में अभूतपूर्व विकास कार्य किए जा रहे हैं। मंडी क्षेत्र में हुए विकास को किसान और व्यापारी प्रत्यक्ष रूप से महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री के नेतृत्व में मंडियों का विकास किसानों के लिए मौल का पथर साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि मजबूत कृषि अधोसंरचना से ग्रामीणी अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी और किसान सशक्त होंगे। उन्होंने राष्ट्रीय किसान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए जय जवान-जय किसान का नारा दिया।

आजात शत्रु रहे अटल बिहारी वाजपेयी : विधायक ललित



अटल परिसर लोकार्पण में जुटी भीड़

रिसाली। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के प्रतिमा अनावरण समारोह में सैकड़ों लोगों ने अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को आजात शत्रु के रूप में परिभाषित किया। उन्होंने वर्चुअल कार्यक्रम रिसाली में बने अटल परिसर का लोकार्पण किया। दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने कहा कि दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे राजनितीज्ञ हैं जिन्हें सुनने अपार भीड़ व विपक्ष के लोग इंतजार

करते थे। उनकी भाषा शैली इतनी सटिक थी कि वे अपनी बात संक्षेप में पूरा करते थे। छत्तीसगढ़ के निर्माता के रूप में वे हमेशा वंदनीय रहेंगे। विधायक ललित ने कहा कि साहित्यकार, पत्रकार जैसे अनेक विधा उन्म में विद्यमान थी। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसे अनेक योजनाओं को विस्तारित करते हुए कहा कि भारत की दिशा और दशा को अटल बिहारी वाजपेयी ने बदली है। इस अवसर पर नगर पालिक निगम रिसाली के सभापति केशव बंछीर, नेता प्रतिपक्ष शैलेन्द्र साहू, पार्षद सविता ढवस, ममता सिन्हा, गजेन्दी कोठारी, सरिता देवांगन, माया यादव, शीला नारखेड़े, खिलेन्द्र चंद्राकर आदि थे।

छत्तीसगढ़ में मंत्रीगणों एवं पुलिस अधिकारियों को गॉर्ड ऑफऑनर दिए जाने की परंपरा समाप्त

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा की विशेष पहल से औपनिवेशिक परंपरा में ऐतिहासिक बदलाव

प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्रीगणों और पुलिस के आला अधिकारियों को सामान्य दौरे, निरीक्षण, भ्रमण के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने की औपनिवेशिक परंपरा को समाप्त कर दिया गया है। गृह विभाग द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर के नियमों में संशोधन किए जाने का आदेश जारी कर दिया गया है। जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री श्री

विजय शर्मा की विशेष पहल पर गृह विभाग ने गार्ड ऑफऑनर की औपनिवेशिक काल से चली आ रही परंपरा को समीक्षा करने के उपरंत इसमें संशोधन का आदेश जारी किया है। इसका उद्देश्य पुलिस बल की कार्यक्षमता का उपयोग कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने और औपनिवेशिक सोच से जुड़ी परंपराओं को समाप्त करना है।

गौरतलब है कि गृहमंत्री श्री विजय शर्मा ने स्वयं विभाग के अधिकारियों को गार्ड ऑफऑनर की वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा कर इसमें वर्तमान स्थिति में आवश्यकतानुसार बदलाव करने के निर्देश दिए थे। जिसके परिपालन में गृह विभाग ने पुलिस बल को अनावश्यक

औपचारिकताओं से मुक्त कर उनकी कार्यक्षमता का उपयोग उनके मूल दायित्वों के पालन के लिए यह संशोधन किया है।

जारी आदेश के तहत राज्य के भीतर सामान्य दौरों, आगमन-प्रस्थान एवं निरीक्षण के दौरान अब गृहमंत्री, समस्त मंत्रीगण, पुलिस महानिदेशक सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सलामी गारद (गार्ड ऑफऑनर) नहीं दिया जाएगा। जिला भ्रमण, दौरे या निरीक्षण के समय पूर्व में प्रचलित सलामी व्यवस्था की पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। इससे पुलिस बल का समय और ऊर्जा का प्रभावी उपयोग सुरक्षा, कानून-व्यवस्था तथा जनसेवा के कार्यों में हो सकेगा।



शासकीय महाविद्यालय अम्बागढ़ चौकी में दो दिवसीय वार्षिक उत्सव एवं पदक वितरण समारोह संपन्न

अबागढ़ चौकी

शासकीय लाल चक्रधर शाह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बागढ़ चौकी में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को दृष्टिगत रखते हुए दो दिवसीय वार्षिक क्रीड़ा, साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं पदक वितरण समारोह का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम के प्रथम दिवस 22 दिसंबर को साहित्यिक क्रीड़ा उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं हेतु विभिन्न खेल प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। विद्यार्थियों ने खेल गतिविधियों में उत्साहपूर्वक सहभागिता कर खेल भावना का परिचय दिया। द्वितीय दिवस 23 दिसंबर को साहित्यिक गतिविधियाँ एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। नृत्य, गीत, नाट्य एवं अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने उपस्थित जनसमुदाय को मंत्रमुग्ध कर दिया। समारोह के शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती नम्रता सिंह



उपस्थित रहीं। विशिष्ट अतिथियों के रूप में गुलाब गोस्वामी, काशीराम निषाद, मोहन जैन, अमित श्रीवास्तव, हितेश जैन, संतोष साहू, विनीत शर्मा, नंदकुमार अमरिया, मनोष साहू (विधायक प्रतिनिधि) तथा डॉ. एन. के. लहरे (सेवानिवृत्त प्राध्यापक) सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान सत्र 2023 एवं 2024 में शैक्षणिक, खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को स्वर्ण

पदक एवं प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। साथ ही राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को महाविद्यालय खेल गौरव सम्मान से अलंकृत किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. के. आर. मंडावी के आदेशानुसार एवं कार्यक्रम अधिकारी जे. आर. परतेती के निर्देशन में आयोजित इस समारोह का उद्देश्य विद्यार्थियों में रचनात्मकता, नेतृत्व क्षमता तथा सांस्कृतिक



चेतना का विकास करना रहा। कार्यक्रम का संचालन श्री ओ. पी. राणा द्वारा किया गया तथा आधार प्रदर्शन ए. एल. चन्द्रभाष ने किया। आयोजन को सफल बनाने में महाविद्यालय के समस्त स्टाफ-डॉ. एन. के. कुरें, डॉ. मोरध्वज सोनवानी, डॉ. मेमन साहू, डॉ. जे. पी. सूर्यवंशी, डी. के. बंजारे, एस. के. देवांगन, श्रीमती सुमित्रा सोनवानी, श्रीमती अंजली कुंजाम, चन्द्रेश साहू, पंकज कुमार एवं अन्य कर्मचारियों का सराहनीय योगदान रहा।

जेम पोर्टल पर खरीदी प्रक्रिया में बरतें पूरी सावधानी : कलेक्टर

ऊर्जा संरक्षण का लिया गया संकल्प

बलौदाबाजार

कलेक्टर दीपक सोनी ने मंगलवार को समय-सीमा की बैठक में विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने जेम पोर्टल पर खरीदी प्रक्रिया में सतर्कता एवं पूरी पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिये। इस दौरान उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को ऊर्जा संरक्षण का संकल्प दिलाया। कलेक्टर श्री सोनी ने कहा कि राज्य शासन की मंशानुरूप शासकीय खरीदी में भण्डार ऋय नियम का कड़ाई से पालन करें। जेम पोर्टल पर टेंडर की प्रक्रिया सावधानी पूर्वक किया जाए। उन्होंने बैठक में धान खरीदी की समीक्षा करते हुए अवैध धान पर सख्त कार्यवाही करने, धान उखाव में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने नोडल अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले सासाहिक निरीक्षण में स्टॉक रजिस्टर एवं भौतिक रूप से उपस्थिति का



मिलान कर रिपोर्ट तैयार करने के भी निर्देश दिये। राजस्व के लंबित प्रकरणों का तेजी से निराकरण करने तथा स्वामित्व योजना अंतर्गत अधिकार अभिलेख पत्र तैयार करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने खाद्य पदार्थों में मिलावट के विरुद्ध कार्यवाही हेतु मिश्रण एवं बेकरी प्रतिष्ठानों में नियमित रूप से जांच अभियान चलाने के निर्देश खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों को दिये। इसी तरह अवैध शराब निर्माण एवं

भण्डारण पर भी नियमित रूप से कार्यवाही करने के निर्देश दिये। इस दौरान मुख्यमंत्री जनदर्शन, मुख्यमंत्री सचिवालय, सीपी ग्राम्स, समय-सीमा से सम्बन्धित आवेदनों के निराकरण में तेजी लाने के निर्देश दिये। बैठक में सीईओ जिला पंचायत सुश्री दिव्या अग्रवाल, अपर कलेक्टर सुश्री दीप्ति गौते, अवध राम टंडन, निशा नेताम मंडवी सहित एसडीएम, जनपद सीईओ एवं विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।

जिले में श्रमिकों का शत-प्रतिशत पंजीयन हो सुनिश्चित-कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति

गुणवत्तापूर्ण हो निर्माण एवं मरम्मत कार्य, छात्रावासों की साफ-सफाई का रखें विशेष ध्यान

कलेक्टर श्रीमती प्रजापति ने समय-सीमा बैठक में विभागीय योजनाओं एवं विकास कार्यों की समीक्षा



मोहला

कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति एवं जिले में संचालित विकास कार्यों की विभागवार विस्तृत समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्रीमती भारती चन्द्राकर, अपर कलेक्टर जीआर मरकाम, एसडीएम मोहला हेमन्त कुमार, एसडीएम मानपुर अमित नाथ योगी, डिप्टी कलेक्टर डीआर ध्रुव सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में कलेक्टर ने आदिवासी

विकास विभाग की समीक्षा करते हुए जिले के समस्त छात्रावासों में साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने छात्रावासों की मरम्मत कार्यों की जानकारी लेते हुए कहा कि मरम्मत कार्य गुणवत्तापूर्ण एवं समय-सीमा में पूर्ण किया जाए। साथ ही एकलव्य आवासीय विद्यालय के निर्माण कार्य की प्रगति की भी समीक्षा की। कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने वर्तमान में चल रही धान खरीदी प्रक्रिया पर चर्चा

दिए। श्रम विभाग की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने जिले के श्रमिकों का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने छूटे हुए श्रमिकों को जागरूक करने हेतु कार्ययोजना बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए, ताकि सभी श्रमिक पंजीकृत होकर शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि पंजीयन नहीं होने से श्रमिक शासन की योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने जिले में संचालित सभी निर्माण कार्यों की जानकारी लेते हुए गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। बैठक में कलेक्टर श्रीमती प्रजापति ने सभी विभागीय अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की गंभीर अनियमितता उजागर, शासन निर्देशों की खुलेआम अवहेलना

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर

भरतपुर के ग्राम पंचायत सिंगरौली अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केंद्र मौहारापारा में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा गंभीर अनियमितता बरते जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि संबंधित कार्यकर्ता शासन के स्पष्ट निर्देशों की अवहेलना करते हुए न कि ग्राम की निवासी न होकर लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूर जनकपुर में निवास करते हुए आंगनबाड़ी का संचालन कर रही हैं।

शासन के महिला एवं बाल विकास विभाग के नियमों के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का उसी ग्राम का निवासी होना अनिवार्य है, जहां वह पदस्थ है। इसके बावजूद उक्त कार्यकर्ता वर्षों से नियमों को ताक पर रखकर कार्य कर रही हैं, जो विभागीय लापरवाही और संरक्षण की ओर भी इशारा करता है।

महीने में केवल 10-15 दिन ड्यूटी, केंद्र अधिकतर बंद-ग्राम सिंगरौली के ग्रामीणों, पंचायत प्रतिनिधियों और पूर्व सरपंच के पति ने आरोप लगाया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महीने में मात्र 10 से 15 दिन ही केंद्र में उपस्थित रहती हैं। शेष दिनों में आंगनबाड़ी केंद्र में ताला लटका रहता है, जिससे छूटे



बच्चों और गर्भवती महिलाओं को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

पद का रौब दिखाकर मनमानी करने का आरोप-ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि संबंधित कार्यकर्ता आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/डुसहायिका सघ की जिला अध्यक्ष हैं और इसी पद का रौब दिखाकर अनियमितता बरत रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि शिकायत करने पर भी कोई सुनवाई नहीं होती, जिससे कार्यकर्ता बेखौफ होकर मनमानी कर रही हैं।

ग्रामीणों की जुबानी सच्चाई-ग्रामीण सीताराम ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बीच-बीच में आती हैं, महीने में लगभग 10-15 दिन ही केंद्र खुलता है। वहीं शिवकुमार ने कहा कि उनका खेत उसी ओर है, लेकिन

आंगनबाड़ी केंद्र अधिकांश समय बंद ही मिलता है। उन्हें समझ नहीं आता कि बच्चों के लिए बना केंद्र आखिर चलता क्यों नहीं। पूर्व सरपंच जगन्नाथ ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि केंद्र लंबे समय से अनियमित है और कार्यकर्ता कभी-कभार ही आती हैं, जो बेहद चिंताजनक स्थिति है।

बच्चों को नहीं मिल रहा पोषण आहार-सरपंच पति शिवलाल ने बताया कि मौहारापारा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में अक्सर ताला लगा रहता है। कार्यकर्ता और सहायिका की अनुपस्थिति के कारण बच्चों को पोषक आहार नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहना गंभीर लापरवाही है और इसकी शिकायत परियोजना कार्यालय में की जाएगी।

प्रशासन हरकत में, जांच के

निर्देश-मामले की गंभीरता को देखते हुए अपर कलेक्टर विनायक शर्मा ने ग्राम पंचायत सिंगरौली के आंगनबाड़ी केंद्र के समय पर नहीं खुलने और बंद रहने की सूचना पर संज्ञान लिया है। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को जांच कर दोषियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

सवालियों के घरे में विभागीय निगरानी-अब बड़ा सवाल यह है कि जब आंगनबाड़ी केंद्र लंबे समय से बंद और अनियमित रूप से संचालित है, तो विभागीय अधिकारियों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण क्यों नहीं किया गया? क्या प्रभावशाली पद होने के कारण कार्यकर्ता को संरक्षण मिला हुआ है? जांच के बाद ही सच्चाई सामने आ सकेगी।

धान खरीदी केन्द्र खैरकट्टा के समिति प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस

कलेक्टर ने डौण्डीलोहारा विकासखण्ड के विभिन्न धान खरीदी केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा

वास्तविक किसानों के वास्तविक रकबे के आधार पर शत प्रतिशत धान की खरीदी करने एवं धान की अवैध खरीदी-बिक्री की रोकथाम हेतु पुख्ता उपाय सुनिश्चित करने के लिए निर्देश



बालोदा। कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने आज डौण्डीलोहारा विकासखण्ड के ग्राम कोडकसा, भंवरमरा, खैरकट्टा, राणा खुज्जी एवं खेरथा के धान खरीदी केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण कर संपूर्ण व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को वास्तविक किसानों के वास्तविक रकबे के आधार पर शत प्रतिशत धान की खरीदी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। श्रीमती मिश्रा ने कहा कि कोई भी पात्र कृषक अपनी वास्तविक रकबे के अनुसार धान की बिक्री करने से वंचित न रहे। इसके अलावा उन्होंने मौके पर उपस्थित नोडल अधिकारी, समिति प्रबंधक एवं अन्य सभी अधिकारी-कर्मचारियों को धान खरीदी केन्द्रों में धान की अवैध खरीदी-बिक्री की रोकथाम सुनिश्चित करने हेतु पुख्ता उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। श्रीमती मिश्रा ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी योजना को राज्य शासन की अत्यंत महत्वाकांक्षी एवं विशेष प्राथमिकता वाले योजना बताते हुए इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरते जाने पर संबंधित

अधिकारी-कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। इस दौरान कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने धान खरीदी केन्द्र खैरकट्टा में बिना कलर के सुतली से धान बोरो की सिलाई किए जाने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। कलेक्टर ने इसके लिए उन्होंने समिति प्रबंधक की जिम्मेदारी तय करते हुए उनके विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने धान खरीदी केन्द्र खैरथा एवं राणा खुज्जी के समिति प्रबंधकों को कार्यप्रणाली में सुधार लाने की चेतावनी भी दी। इस दौरान उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ श्री आरपी राठिया, तहसीलदार श्री हिंसराम नायक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के नोडल अधिकारी श्री सीआर रावटे सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने धान खरीदी

केन्द्रों के निरीक्षण के दौरान दस्तावेजों का अवलोकन कर धान खरीदी केन्द्रों में अब तक खरीदे गए धान की कुल मात्रा, ग्रामवार औसत पैदावार, रकबा समर्पण की स्थिति आदि का सूक्ष्मता से पड़ताल किया। कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने मौके पर उपस्थित अधिकारी-कर्मचारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में कोचियों, व्यापारी आदि से धान की अवैध खरीदी न की जाए। श्रीमती मिश्रा ने इस संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की भी चेतावनी दी। कलेक्टर ने धान खरीदी केन्द्रों में रकबा समर्पण कराने वाले किसानों की कुल संख्या की जानकारी लेते हुए रकबा समर्पण के कार्य को विशेष प्राथमिकता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अंतर्गत उन्होंने धान बिक्री करने के पश्चात् जिन कृषकों के पास धान शेष नहीं रह जाता उनका अनिवार्य रूप से रकबा

समर्पण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि पहले टोकन के पश्चात किसानों के रकबा के आधार पर पात्रानुसार उनका दूसरा एवं तीसरा टोकन काटे जाने पर भौतिक सत्यापन के उपरांत ही संबंधित कृषकों को धान की खरीदी करने के निर्देश दिए। श्रीमती मिश्रा ने दूसरा एवं तीसरा टोकन जारी करने की स्थिति में निगरानी दल में शामिल हल्का पटवारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, ग्राम पंचायत सचिव आदि अधिकारी-कर्मचारियों को संबंधित किसानों के घरों में भेजकर उनके पास उपलब्ध धान की भौतिक सत्यापन कराने को कहा। जिससे कि केवल वास्तविक किसानों के वास्तविक धान की खरीदी सुनिश्चित होने के साथ-साथ व्यापारियों एवं कोचियों से चर्चा कर धान खरीदी केन्द्र की अवैध खरीदी-बिक्री पर रोकथाम सुनिश्चित की जा सके। इस दौरान कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने धान खरीदी केन्द्र में उपस्थित किसानों के निर्देश भी दिए। इस मौके पर कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने धान खरीदी केन्द्रों में धान बोरो के तौल का अवलोकन किया। उन्होंने नमी मापक यंत्र के माध्यम से धान की नमी की भी जांच कराया। सभी धान खरीदी केन्द्रों में धान में नमी की मात्रा समुचित पाई गई।

राशन के लिए हितग्राही खाद्य विभाग व राशन दुकानों के चक्कर काटने विवश



ई-केवायसी बनी हितग्राहियों की समस्या, खाद्य विभाग भी समस्या समाधान में असमर्थ

दुर्ग। शासन के सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत बोपीएल और एपीए राशन कार्ड के कई पात्र हितग्राहियों को पिछले दो-तीन माह से राशन दुकानों से राशन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जिसकी वजह से हितग्राही राशन दुकानों व खाद्य विभाग का चक्कर काटने विवश है, लेकिन उनकी समस्याएं जस की तस बनी हुई है। फलस्वरूप खाद्य विभाग की कार्यशैली के खिलाफ हितग्राहियों का आक्रोश बढ़ने लगा है। यही आक्रोश बुधवार को हितग्राहियों का खाद्य विभाग में देखने में सामने आया, जब राशन नहीं मिलने से नाराज हितग्राही बड़ी संख्या में खाद्य विभाग के कार्यालय में पहुंचे थे और इसे लेकर अपनी जमकर नाराजगी जताई। खबर पर राशन कार्ड हितग्राहियों की समस्याओं

को लेकर पूर्व विधायक अरुण चोरा और पूर्व महापौर आरएन वर्मा भी खाद्य विभाग के दफ्तर पहुंचे थे। उन्होंने राशन दुकानों से राशन नहीं मिलने को हितग्राहियों के साथ बड़ा अन्याय बताया और व्यवस्था सुधारकर तत्काल हितग्राहियों को राशन उपलब्ध करवाने पर जोर दिया। खाद्य विभाग पहुंचने पर जनप्रतिनिधियों और हितग्राहियों की मुलाकात खाद्य नियंत्रक से नहीं हो पाई। उनकी अनुपस्थिति में सहायक खाद्य अधिकारी वसुंधरा गुप्ता ने उन्हें बताया कि ई-केवायसी नहीं करवाने की वजह से ऐसे हितग्राहियों को राशन का आबंटन नहीं हो पा रहा है। परिवार के एक सदस्य का भी ई-केवायसी नहीं होने की स्थिति पर राशन नहीं मिलेगा। इस पर हितग्राहियों ने सहायक खाद्य अधिकारी से सवाल-जवाब भी किया और हितग्राहियों ने कहा कि अभी 6 महीने पहले ही परिवार के सदस्यों का ई-केवायसी करवाया गया था।

परिवार के बुजुर्ग सदस्यों व बच्चों का तकनीकी खामियों की वजह से ई-केवायसी नहीं हो पाया था। अगर परिवार के एक सदस्य का ई-केवायसी नहीं हुआ है, तो परिवार को राशन देना बंद कर देना गरीब परिवार के साथ अन्याय है। शासन व प्रशासन को इसका विकल्प निकालकर राशन कार्डधारियों को राशन आबंटन कर राहत प्रदान करनी चाहिए, ना कि राशन देना बंद कर देना चाहिए। हितग्राहियों के सवाल के जवाब में सहायक खाद्य अधिकारी वसुंधरा गुप्ता का कहना था कि ई-केवायसी के इस समस्या के समाधान के लिए ई-केवायसी से छूटे परिवार के बुजुर्ग सदस्यों व बच्चों का आधार कार्ड व परिवार के राशन की छायाप्रति विभाग द्वारा एकत्रित की जा रही है। केवायसी से छूटे ऐसे सदस्यों का लिस्टिंग कर समस्या समाधान के लिए शासन से मार्गदर्शन मांगा जाएगा ताकि कोई भी पात्र हितग्राही राशन लेने से वंचित ना हो सके।

भोरमदेव शक्कर कारखाना में बनाए जाएंगे नए अंशधारी सदस्य, किसानों को मिलेगा सीधा लाभ

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के सतत प्रयासों से कारखाना क्षेत्र के गन्ना किसानों को मिल रहा निरंतर लाभ

कवर्धा

भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित, कवर्धा में अब नए अंशधारी सदस्य बनाए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक विजय शर्मा के सतत प्रयासों से कारखाना क्षेत्र के गन्ना किसानों को निरंतर लाभ मिल रहा है। पेराई सत्र 2023-24 एवं 2024-25 के दौरान कारखाना द्वारा गन्ना किसानों को 300 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया। वहीं वर्तमान पेराई सत्र 2025-26 में अब तक 17.51 करोड़ रुपये का भुगतान किसानों को किया जा चुका है। इस पेराई सत्र में कारखाना द्वारा 4.50 लाख मीट्रिक टन गन्ना पेराई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के विशेष पहल के परिणामस्वरूप विगत दो वर्षों से अंशधारी सदस्यों को रियायती दर पर शक्कर

का वितरण किया जा रहा है, जिससे अंशधारी सदस्यों में उत्साह का वातावरण है। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 9 की उपधारा (1) के अंतर्गत पंजीकृत भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित, कवर्धा (पंजीयन दिनांक 03.04.2001) में वर्तमान में कुल 23,476 अंशधारी सदस्य हैं। इनमें कबीरधाम जिले के तीन विकासखंडों के कृषक सदस्य ही गन्ने की आपूर्ति करते हैं। विगत कुछ वर्षों से लक्ष्यानुसार गन्ना आपूर्ति नहीं होने के कारण कारखाना को समय से पूर्व पेराई बंद करनी पड़ी। पेराई सत्र 2024-25 में जनवरी माह से गन्ना आपूर्ति में कठिनाइयां आईं, जिससे फरवरी 2025 में ही पेराई सत्र समाप्त करना पड़ा और ब्रेक ईवन प्वाइंट की पूर्ति नहीं हो सकी। कारखाना के ब्रेक ईवन प्वाइंट हेतु कम से कम 4.00 लाख टन गन्ना पेराई आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए कारखाना प्रबंधन द्वारा नए अंशधारी सदस्य

बनाए जाने की कार्ययोजना तैयार की गई है। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम गैर-अंशधारी किसानों से 02 ट्राली गन्ने की खरीदी की जाएगी, तत्पश्चात संबंधित कृषक को अंशधारी सदस्यता प्रदान की जाएगी। इससे वर्षों से चली आ रही किसानों की अंशधारी सदस्य बनने की मांग पूरी होगी। इस निर्णय से गन्ना कृषकों में हर्ष व्याप्त है। अंशधारी सदस्य बनने पर किसानों को गन्ना विक्रय, रियायती दर पर शक्कर, प्रेसमड एवं कारखाना द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा। कारखाना में वर्तमान में 23,476 अंशधारी सदस्यों में से लगभग 12,500 से 13,000 सदस्य ही गन्ने की खेती कर कारखाना में गन्ना विक्रय कर रहे हैं। शेष अंशधारी सदस्य न तो गन्ना विक्रय कर रहे हैं और न ही संस्था की उपविधियों के अनुरूप दायित्वों का पालन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अंशधारी सदस्य सर्वे कराने के पश्चात भी कारखाना में गन्ना न देकर गुड़ फैक्ट्रियों में गन्ना विक्रय कर देते

हैं, जिससे कारखाना को लक्ष्यानुसार गन्ना प्राप्त नहीं हो पाता और पेराई सत्र समय से पूर्व बंद करना पड़ता है। ऐसे अंशधारी सदस्यों की संस्था की उपविधियों के अनुसार सदस्यता समाप्त करने की कार्यवाही कारखाना प्रबंधन द्वारा की जाएगी। सदस्यता समाप्त होने की स्थिति में भविष्य में वे कारखाना में गन्ना विक्रय, रियायती शक्कर, प्रेसमड एवं अन्य सुविधाओं से वंचित रहेंगे। गन्ना उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना के कार्यक्षेत्र में गन्ना विकास कार्य एवं बीज प्रतिस्थापन कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। आधुनिक तकनीकों के माध्यम से कवर्धा जिले की जलवायु के अनुकूल उच्च उपज देने वाली नई किस्मों का चयन कर उन्नत गन्ना बीज का रोपण कराया जा रहा है। विगत वर्ष भी कारखाना द्वारा उत्तरप्रदेश एवं महाराष्ट्र से गन्ने की नई किस्में मंगवाकर लगभग 60 एकड़ क्षेत्र में किसानों को बीज के रूप में वितरित किया गया था।

पामगढ़

ठेठवार यादव समाज बरतोरी राज के तत्वावधान में वार्षिक कैलेंडर विमोचन एवं प्रतिभावान छात्र-छात्राओं का सम्मान समारोह आगामी 24 दिसंबर 2025 बुधवार को ग्राम कुंवापाली ग्राम पंचायत खम्हारडीह में आयोजित किया जाएगा, यह एक दिवसीय सामाजिक सम्मेलन समाज की एकता, शिक्षा और सांस्कृतिक चेतना को सशक्त करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत समाज के वर्ष 2025 के कक्षा 10 वीं एवं 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में स्वजाति बंधु उपस्थित रहेंगे। समारोह के मुख्य अतिथि माननीय डॉ. गोविंद यादव सभापति जिला पंचायत बिलासपुर होंगे,अति विशिष्ट अतिथि के रूप में



संदीप यादव उपाध्यक्ष छ.ग. ठेठवार यादव महासभा भाटापारा अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराएंगे,कार्यक्रम की अध्यक्षता राज प्रमुख तुमश यादव करेंगे वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में भरत लाल यादव अध्यक्ष संतोष कुमार यादव सलाहकार महासभा सोखन यादव देवान सरोज चंद्रप्रकाश यादव सरपंच रमेश यादव सचिव यादव समाज लंकेश यादव कोषाध्यक्ष बरतोरी राज व सचिव ग्राम पंचायत ससहा जगत यादव उपाध्यक्ष देवचरण यादव उपाध्यक्ष अमित यादव

सलाहकार हृदय यादव प्रवक्ता शत्रुहन यादव पुर्व अध्यक्ष रामधुनी यादव सहसचिव श्यामलाल यादव सहसचिव रहेंगे। आयोजकों ने समाज के सभी गणमाय्य नागरिकों, युवाओं एवं मातृशक्ति से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाएं तथा देवान सरोज चंद्रप्रकाश यादव उज्जयन के संकल्प को मजबूती प्रदान करें एक सशक्त समाज में नवाचार के प्रयोग से नव पीढ़ी को समाज के गतिविधियों से जोड़ने का प्रयाश आयोजकों द्वारा किया जा रहा है।

हंगवा में श्रम पंजीयन शिविर का हुआ आयोजन, 82 श्रमिकों का हुआ पंजीयन एवं नवीनीकरण

कोण्डगांव

छत्तीसगढ़ शासन की मंशा के अनुरूप एवं कलेक्टर श्रीमती नूपुर राशि पन्ना के निर्देशानुसार जिला कोण्डगांव में निर्माण श्रमिकों एवं असंगठित कर्मकारों के पंजीयन, नवीनीकरण तथा विभागीय योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विकासखंड कोंडगांव के ग्राम पंचायत हंगवा में मोबाइल पंजीयन एवं नवीनीकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन कार्यालय श्रम पदाधिकारी, जिला कोण्डगांव द्वारा किया गया, जिसमें कुल 82 श्रमिकों का पंजीयन एवं नवीनीकरण किया गया। इस अवसर पर श्रमिकों को श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी



योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। शिविर में नौनिहाल छत्रवृत्ति योजना, मिनीमाता महतारी जनत योजना, नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता

योजना सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के लाभ, पात्रता एवं आवेदन प्रक्रिया के बारे में बताया गया। अधिकारियों ने श्रमिकों से अधिक से अधिक संख्या में पंजीयन करारक योजनाओं का लाभ लेने की

बलौदाबाजार

नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन एवं कलेक्टरदीपक सोनी के निर्देशानुसार किसमस व नये साल को देखते हुये ग्राहकों को सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने हेतु लगातार नमूना संकलन व निरीक्षण का कार्य किया जा रहा है। इसी कम में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा जिले के विभिन्न खाद्य संस्थानों का निरीक्षण एवं जांच कर सैम्पल लेकर जांच हेतु राज्य प्रयोगशाला भेजा गया। निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी कंचन वर्मा ने बलौदाबाजार म स्थित माय बेकर्स से ब्लैक फ़ैस्ट केक, लाला डेयरी से पनीर तथा होटल पार्क प्लाजा से बेज बिरयानी तथा दाल



फाई का नमूना लिया। संस्था महिलांग ने भाटापारा स्थित द केक बॉक्स से चाकलेट केक तथा सिमगा स्थित संगम डेयरी से पनीर, मीठा दही व दूध का नमूना संकलन किया गया है। उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना संकलन कर जांच हेतु राज्य संकलन कर जांच हेतु राज्य सभापति जिला पंचायत सभापति डॉ.वीरेन्द्र साहू ,उपाध्यक्ष गणेश तिवारी, सडक एवं अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित समयाएँ रखी गईं। प्राप्त आवेदनों पर संबंधित विभागों द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए कई समस्याओं का मौके के ही निराकरण किया गया तथा शेष मामलों में समय-समया निर्धारित कर शीघ्र समाधान के निर्देश दिए गए।



साहू संघ के निर्विरोध जिलाध्यक्ष बने जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू

जांजगीर-चांपा

जिला साहू संघ जांजगीर-चांपा के चुनाव में जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू को सर्वसम्मति से निर्विरोध जिलाध्यक्ष चुना गया। उल्लेखनीय है कि विधायक बालेश्वर साहू लगातार दूसरी बार इस पद पर निर्वाचित हुए हैं, जिससे समाज में उनके नेतृत्व और कार्यों पर विश्वास स्पष्ट दिखाई देता है। चुनाव के दौरान अन्य पदाधिकारियों का चयन भी निर्विरोध संपन्न हुआ, जिसमें उपाध्यक्ष पद पर प्रेमशंकर साहू एवं सुभद्रा साहू को चुना गया, वहीं संगठन सचिव की जिम्मेदारी फिरत साहू, रत्ना साहू को सौंपी गई। निर्वाचन प्रक्रिया में पर्यवेक्षक शान्तनु साहू, सहायक पर्यवेक्षक कामता साहू एवं चुनेंद्र साहू की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वहीं निर्वाचन अधिकारी केशव साहू तथा सह निर्वाचन अधिकारी रामचरण साहू और सुशील साहू ने चुनाव को



सफलतापूर्वक संपन्न कराया। इसअवसर पर नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष बालेश्वर साहू ने समाज के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे सभी को साथ लेकर साहू समाज के हित में निरंतर कार्य करते रहेंगे। निर्वाचन के बाद समाज के लोगों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाइयां देते हुए संगठन को और अधिक सशक्त व सक्रिय बनाने की

भटगांव में विधानसभा स्तरीय संगठनात्मक कार्यशाला सपन्न

■ संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर हुआ व्यापक मंथन

सूरजपुर/भटगांव

राष्ट्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार भटगांव मंडल के सामुदायिक भवन में विधानसभा स्तरीय संगठनात्मक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य संगठनात्मक ढाँचे को सुदृढ़ करना, बूथ स्तर पर सक्रियता बढ़ाना और आगामी कार्यक्रमों की रणनीति तय करना रहा।

वरिष्ठ नेताओं की सहभागिता

कार्यशाला में जिला प्रभारी शिवनाथ यादव, कार्यक्रम प्रभारी एवं हस्तलिपि बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अनिल सिंह, वन विकास निगम के अध्यक्ष रामसेवक पैकरा, अजन्ना मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सतनारायण सिंह, पूर्व विधायक रजनी रविशंकर



त्रिपाठी, पूर्व जिला अध्यक्ष अजय गोयल तथा भाजपा जिला अध्यक्ष मुरली मनोहर सोनी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

संगठनात्मक विषयों पर चर्चा

इस अवसर पर रेड क्रॉस सोसायटी के जिला अध्यक्ष बाबूलाल अग्रवाल, जिला महामंत्री अशोक सिंह, शशीकांत मणि बग्गा गर्ग, जिला उपाध्यक्ष महेश्वर पैकरा, देवधन बिड़िया, राजेश्वर तिवारी, ललित गोयल, अशोक अग्रवाल, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष नूतन विश्वास, आदिवासी मोर्चा जिला अध्यक्ष अजय श्याम सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे।

बूथ और शक्ति केंद्र पर विशेष फोकस

कार्यशाला में मंडल अध्यक्ष रमेश गुप्ता, सत्यनारायण पैकरा, सुनील साहू, ठाकुर पैकरा, हरीश राजवाड़े, जगसाय सिंह, पूर्व मंडल अध्यक्ष परहित बैस, राजेश तिवारी, सुभाष राजवाड़े, मोहन शर्मा सहित शक्ति केंद्र प्रभारी, संयोजक, सह-संयोजक, बूथ अध्यक्ष एवं बीएलओ-2 ने सक्रिय सहभागिता निभाई।

सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी

कार्यशाला में सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नेताओं ने संगठनात्मक अनुशासन, समन्वय और जनसंपर्क की और अधिक प्रभावी बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि मजबूत संगठन ही चुनावी सफलता की कुंजी है।

ग्राम थुहापानी में कृत्रिम मधुमखी पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन



कवर्धा

कलेक्टर जिला कबीरधाम के तत्वाधान में जिला खनिज न्यास मद अंतर्गत आकांक्षी विकास खण्ड बोड़ला की ग्राम पंचायत चौरभट्टी के आश्रित ग्राम थुहापानी में आजीविका संवर्धन हेतु कृत्रिम मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन समाज के वनमंडलाधिकारी कवर्धा के निर्देशन, उपवनमंडलाधिकारी कवर्धा के

मार्गदर्शन एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी कवर्धा के नेतृत्व में किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में एनजीओ ग्राम विकास खोज केन्द्र मंडला द्वारा चर्यानित हितग्राहियों को कृत्रिम मधुमक्खी पालन की उन्नत एवं वैज्ञानिक तकनीकों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि कृत्रिम मधुमक्खी पालन से न केवल हितग्राहियों को अतिरिक्त आय के अवसर प्राप्त होंगे, बल्कि प्राकृतिक परागण के माध्यम से कृषि उत्पादकता

में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इस अवसर पर चर्यानित 20 हितग्राहियों को मधुमक्खी पालन किट का वितरण किया गया। आगामी चरण में अन्य हितग्राहियों को भी प्रशिक्षण एवं किट वितरण किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, शहद प्रसंस्करण केन्द्र बोड़ला के माध्यम से मधुमक्खी पालन किट से उत्पादित शहद का प्रसंस्करण किया जाएगा, जिससे ग्रामीणों की आजीविका सुदृढ़ एवं सुनिश्चित होगी। इस कार्यक्रम में वन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे।

रेडक्रॉस सोसायटी की कार्यप्रणाली कटघरे में पारदर्शिता और लंबित ऑडिट पर प्रशासन सख्त, तीन सदस्यीय जांच दल गठित

सूरजपुर

जनसहयोग से संचालित रेडक्रॉस सोसायटी की कार्यशैली को लेकर सूरजपुर जिले में हलचल तेज हो गई है। लंबे समय से ऑडिट लंबित रहने और वित्तीय पारदर्शिता पर उठ रहे सवालों के बीच अब प्रशासन ने ठोस कदम उठाया है। रेडक्रॉस सोसायटी के चेयरमैन बाबूलाल अग्रवाल की शिकायत पर कलेक्टर, सूरजपुर ने तीन सदस्यीय संयुक्त जांच दल का गठन कर दिया है।

जनसहयोग की संस्था, जवाबदेही अनिवार्य- रेडक्रॉस सोसायटी के चेयरमैन बाबूलाल अग्रवाल ने कलेक्टर को भेजे पत्र में स्पष्ट किया कि रेडक्रॉस सोसायटी जनसहयोग और जनविश्वास पर आधारित संस्था है। ऐसे में इसके प्रत्येक निर्णय, खर्च और गतिविधियों में पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि जिले में लंबे समय से सोसायटी



का ऑडिट नहीं कराया गया है, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। **आय-व्यय और बैठकों पर उठे सवाल-** पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि सोसायटी की बैठकों, आय-व्यय के विवरण और खर्चों को लेकर स्पष्ट जानकारी समय पर उपलब्ध नहीं कराई जा रही थी। इन मुद्दों को चेयरमैन द्वारा बैठकों में भी उठाया गया, ताकि कार्यप्रणाली को नियमसम्मत और पारदर्शी बनाया जा सके, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ।

कलेक्टर ने लिया तत्काल संज्ञान-मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर के निर्देश पर कार्यालय कलेक्टर (शिकायत शाखा) ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संयुक्त जांच दल का गठन किया। इस निर्णय को प्रशासनिक सख्ती और पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

अपर कलेक्टर के नेतृत्व में जांच-गठित

जांच दल की अध्यक्षता अपर कलेक्टर जगन्नाथ वर्मा करेंगे। दल में जिला कोषालय अधिकारी कार्यालय से प्रेमशंकर तिवारी तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. कपिलदेव पैकरा को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

बैंक खाते, अनुदान और ऑडिट की होगी जांच-जांच दल को रेडक्रॉस सोसायटी के आय-व्यय, अनुदान की उपयोगिता, बैंक खातों के संचालन और लंबे समय से लंबित ऑडिट से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच कर शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

जनहित में अहम पहल, बड़ेगी पारदर्शिता-जांच दल गठन की जानकारी सामने आने के बाद जिले में जनचर्चा तेज हो गई है। जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि इस कार्रवाई से न केवल रेडक्रॉस सोसायटी की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी, बल्कि भविष्य में जनसहयोग से संचालित अन्य संस्थाओं के लिए भी जवाबदेही का स्पष्ट संदेश जाएगा।

जनादेश परब: केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा एवं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की गरिमामयी उपस्थिति में 51 हजार परिवारों के सपनों का घर हुआ साकार

प्रदेश में 51 हजार सहित जांजगीर-चांपा में 1837 परिवारों ने किया गृह प्रवेश

जांजगीर-चांपा

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के पक्के घर का सपना साकार करने की दिशा में आज एक ऐतिहासिक क्षण साक्षी बना। 22 दिसम्बर 2025 को जांजगीर-चांपा जिले में आयोजित जनादेश परब के अवसर पर केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा एवं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं मंत्रीमंडल, सांसद, विधायक एवं जनप्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति में प्रदेश के 51,000 नव निर्मित प्रधानमंत्री आवासों (ग्रामीण) का एक साथ गृह प्रवेश हुआ। इस दौरान प्रदेश के समस्त जिलों में ग्राम स्तर पर भी नव निर्मित आवासों का गृह प्रवेश उत्साह एवं उत्सव के साथ आयोजित किया गया। इस प्रसन्न ग्राम पंचायत में यह कार्यक्रम हितग्राही परिवारों के साथ एक उत्सव



के रूप में मनाया गया, जहां वर्षों का इंतजार आज खुशियों में बदलता नजर आया। इस दौरान जिले में 1,837 नव निर्मित प्रधानमंत्री आवासों का विधिवत गृह प्रवेश कराया गया। जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में आयोजित कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों, पंचायत पदाधिकारियों, ग्रामीणजनों

सुरक्षित जीवन, सामाजिक गरिमा एवं स्थायी आवास की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता का सशक्त प्रतीक बना। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ने एक बार फिर यह सिद्ध किया कि शासन की योजनाएं धरातल पर उतरकर ज़रूरतमंदों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन ला रही हैं।

' जी राम जी: ग्रामीण भारत में विश्वास और उम्मीद '



डॉ. प्रियंका सौरभ

वर्तमान सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट है-विकास को केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रखा जाए। इसके लिए योजना का कायमी प्रभाव और पारदर्शी क्रियान्वयन आवश्यक है। इसके तहत ग्रामीण रोजगार, खाद्यान्न वितरण, महिला सशक्तिकरण और न्यूनतम आय सुरक्षा जैसी नीतियाँ लागू की गई हैं। इन नीतियों के परिणामस्वरूप ग्रामीण और वंचित वर्ग में भरोसा और उम्मीद दोनों बढ़ी हैं।

भारत की राजनीति में विश्वास केवल एक शब्द नहीं, बल्कि जन-धारणाओं और नीतिगत परिणामों का प्रतिफल है। 'विकसित भारत-जी राम जी' बिल और उससे जुड़ी योजनाएँ इस विश्वास की कसौटी पर खड़ी हैं। जब केंद्र सरकार ने यह बिल संसद में प्रस्तुत किया, तो उसके पीछे सतत विकास, सामाजिक न्याय और ग्रामीण कल्याण के विचार थे। यह बिल केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि 125 करोड़ लोगों तक पहुँचने वाली योजनाओं का प्रतीक है। वर्तमान सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट है-विकास को केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रखा जाए। इसके लिए योजना का कायमी प्रभाव और पारदर्शी क्रियान्वयन आवश्यक है। इसके तहत ग्रामीण रोजगार, खाद्यान्न वितरण, महिला सशक्तिकरण और न्यूनतम आय सुरक्षा जैसी नीतियाँ लागू की गई हैं। इन नीतियों के परिणामस्वरूप ग्रामीण और वंचित वर्ग में भरोसा और उम्मीद दोनों बढ़ी हैं।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमेशा असुरक्षित रही है। कृषि पर आधारित जीवन शैली, सीमित औद्योगिक विकास और मौसमी रोजगार की अस्थिरता ने ग्रामीणों को अस्थायी रोजगार और पलायन की ओर मजबूर किया। इस संदर्भ में, केंद्र सरकार की ग्रामीण रोजगार योजना एक जागरूक प्रयास है।

यह योजना न केवल रोजगार उपलब्ध कराती है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निर्माण और उत्पादन गतिविधियों को भी बढ़ावा देती है। महिलाओं की भागीदारी, युवा शक्ति का नियोजन और स्थानीय संसाधनों का उपयोग, योजना को स्थायी और प्रभावी बनाता है। इसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि ग्रामीण आर्थिक सुरक्षा महसूस करें और पलायन कम हो। महिलाओं का भाग्य सुधारना केवल सामाजिक न्याय का सवाल नहीं, बल्कि आर्थिक विकास और सामुदायिक स्थिरता का भी संकेत है। 'जी राम जी' योजना के तहत महिलाओं को रोजगार और प्रशिक्षण के अवसर दिए गए हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव देखा जा सकता है-महिलाओं ने अपने परिवार की आय में योगदान बढ़ाया, स्थानीय उत्पादकता में हिस्सेदारी ली, और अपने समाज में निर्णय लेने की क्षमता विकसित की।



महिला सशक्तिकरण का यह आयाम योजना की दीर्घकालिक सफलता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जब महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है, तो परिवार के स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के मानक भी सुधरते हैं। इस तरह, योजना केवल आर्थिक सुधार तक सीमित नहीं रहती, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की नींव भी तैयार करती है। भारत में खाद्य सुरक्षा हमेशा सामाजिक राजनीति का केंद्र रही है। गरीब और वंचित वर्ग को आवश्यक खाद्यान्न और न्यूनतम आय सुरक्षा प्रदान करना केवल दान या राहत नहीं, बल्कि न्याय और संवैधानिक जिम्मेदारी है। जी राम जी बिल ने इस दिशा में कदम बढ़ाए। 125 करोड़ लाभार्थियों तक पहुँचने वाली योजना का प्रत्यक्ष परिणाम यह है कि भोजन और आय का भरोसा पैदा हुआ है। गरीब वर्ग अब केवल दिन-प्रतिदिन के संघर्ष में नहीं फँसा है, बल्कि भविष्य की योजनाओं में भागीदारी और उम्मीद महसूस करता है। यह भरोसा सरकार और जनता के बीच संबंध की मजबूती का परिचायक है।

सभी नीतियों में आलोचना होना स्वाभाविक है। विपक्ष ने सवाल उठाया है कि-क्या यह योजना दीर्घकालिक आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए पर्याप्त है? क्या यह केवल अस्थायी राहत है? क्या इसके क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित है? इन सवालों का महत्व है। विकास केवल तुरंत परिणामों से मापा नहीं जा सकता। इसे स्थायित्व, निगरानी और समयबद्ध सुधार के साथ देखा जाना चाहिए। आलोचना यह भी याद दिलाती है कि राजनीतिक विश्वास स्थायी तभी बनता है जब योजना के परिणाम लगातार दिखाई दें और जनता के अनुभव से मेल खाते हों। राजनीतिक विश्वास केवल चुनावी रैलियों या भाषणों से नहीं बनता। यह तब मजबूत होता है जब जनता नतीजे देखे, अनुभव करें और महसूस करें। 'जी राम जी' योजना इस दृष्टि से अनूठी है-यह दिखाती है कि यदि सरकार व्यवस्था, नीति और क्रियान्वयन को संतुलित रखे, तो जनता का भरोसा बढ़ सकता है।

साथ ही, यह भी महत्वपूर्ण है कि सरकार सतत निगरानी

उपभोक्ता जागरुकता से समृद्ध समाज की ओर - जागरूक होंगे, तभी मिलेगा इंसाफ



उनकी शक्तियों और अधिकारों के बारे में जागरूक करने का महत्वपूर्व अवसर है। भारत में उपभोक्ता आन्दोलन की शुरूआत मुम्बई में वर्ष 1966 में हुई थी। तत्पश्चात् पुणे में वर्ष 1974 में ग्राहक पंचायत की स्थापना के बाद कई राज्यों में उपभोक्ता कल्याण के लिए संस्थाओं का गठन किया गया। इस प्रकार उपभोक्ता हितों के संरक्षण की दिशा में यह आन्दोलन आगे बढ़ता गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पहल पर 9 दिसम्बर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण विधेयक पारित किया गया, जिसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बार 24 दिसम्बर 1986 को देशभर में लागू किया गया। पिछले कई वर्षों से भारत में प्रतिवर्ष इसी दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस मनाए जाने का मूल उद्देश्य यही है कि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए और अगर वे धोखाधड़ी, कालाबाजारी, घटती हुई इत्यादि के शिकार होते हैं तो वे इसकी शिकायत उपभोक्ता अदालत में कर सकें।

उपभोक्ता संरक्षण कानून में स्पष्ट उल्लेख है कि प्रत्येक वह व्यक्ति उपभोक्ता है, जिसने किसी वस्तु या सेवा के क्रय के बदले धन का भुगतान किया है या भुगतान करने का आशवासन दिया है और ऐसे में किसी भी प्रकार के

शोषण अथवा उसीइन के खिलाफ वह अपनी आवाज उठा सकता है तथा क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है। खरीदी गई किसी वस्तु, उत्पाद अथवा सेवा में कमी या उसके कारण होने वाली किसी भी प्रकार की हानि के बदले उपभोक्ताओं को मिला कानूनी संरक्षण ही उपभोक्ता अधिकार है। यदि खरीदी गई किसी वस्तु या सेवा में कोई कमी है या उससे आपको कोई नुकसान हुआ है तो आप उपभोक्ता फोरम में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ने उपभोक्ताओं को छह प्रमुख अधिकार प्रदान किए हैं, जिनमें सुरक्षा का अधिकार के तहत खरनक वस्तुओं और सेवाओं से बचाव का अधिकार, सूचना का अधिकार के तहत वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता और कीमत की सही जानकारी का अधिकार, विकल्प का अधिकार के तहत प्रतिस्पर्धात्मक कीमतों पर वस्तुओं और सेवाओं का चयन का अधिकार, सुने जाने का अधिकार के तहत उपभोक्ता की शिकायतों और समस्याओं पर ध्यान दिया जाना का अधिकार, निवारण का अधिकार के तहत उपभोक्ता की शिकायतों और समस्याओं पर ध्यान दिया जाना का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार के तहत अनुचित व्यापार प्रथाओं

भारतीय राजनीति में चयनात्मक संवेदनशीलता

तुष्टिकरण की शिकार भारतीय राजनीति में इसका चर्चा तक नहीं होता। लेकिन यदि किसी अल्पसंख्यक पर, खासकर मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति के साथ सात समुंदर पर भी कोई घटना घटित हो जाए तो भारत में हाव तौबा मच जाती है। हमें याद करना होगा, जब इजरायल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष होता है, तो भारत की सड़कों से लेकर संसद तक विरोध की लहर देखी जाती है। मानवाधिकारों के नाम पर रैलियां निकाली जाती हैं और विदेशी धरती पर हो रहे अन्याय के खिलाफ भारतीय नेता मुखर होकर बयान देते हैं। निरसंहदेह, निदोषों की जान कहीं भी जाए, वह दुःख है। लेकिन प्रश्न तब उठता है जब पड़ोस के देश बांग्लादेश में, जहाँ की संस्कृति और इतिहास भारत से गहराई से जुड़े हुए हैं, वहां हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर अधिकांश नेता मौन साध लेते हैं। क्या ढाका में मरने वाले दीपचंद का जीवन गाजा में मरने वाले किसी व्यक्ति से कम मूल्यवान है? बेशक नहीं, किंतु तुष्टीकरण की राजनीति और चयनात्मक संवेदनशीलता इस भेदभाव को उजागर तो करती ही है। स्पष्ट तौर पर लिखा जाए तो यह सत्य है कि भारतीय राजनीति में सेकुलरिज्म अर्थात पंथ निरपेक्षता की परिभाषा वोट बैंक के समीकरण में उलझ कर रह गई है। जब किसी घटना में पीड़ित पक्ष बहुसंख्यक समुदाय (हिंदू) से होता है, तो कई राजनीतिक दल इसे दूसरे देश का आंतरिक मामला कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं। इसके विपरीत, यदि पीड़ित पक्ष किसी विविष्ट अल्पसंख्यक समुदाय से हो, तो उसे तुरंत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों के चरम से देखा जाने लगता है। भारतीय राजनीति में नुकसान और फायदे

की सोच के चलते ऐसी प्रमुख विसंगतियाँ व्यापक पैमाने पर स्थापित हो गई हैं। इसे क्रियान्वयनों एवंप्रदर्शनों का दोहरा मापदंड भी कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए स्वीडन में कुरान जलाने की घटना पर गौर किया जाना उचित रहेगा। हजारों किलोमीटर दूर उस राष्ट्र में मुस्लिम समाज का पवित्र ग्रंथ कुरान जलाया जाता है, लेकिन भारत के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शनों होते हैं। वहीं जब पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में मंदिरों को तोड़ा जाता है, हिंदुओं की हत्या की जाती है, उनके घर जला दिए जाते हैं हिंदू महिलाओं बालिकाओं के बलात्कार होते हैं, तब अधिकांश भारतीय राजनेताओं और राजनीतिक दलों की तीखी एवं त्वरित प्रतिक्रिया नदारद बनी रहती है। ऐसे में आक्रामक बयानों का तो एक प्रकार से अकाल ही पड़ जाता है। फिलिस्तीन के समर्थन में ट्वीट करने वाले मानवाधिकार कार्यकर्ता और राजनेता बांग्लादेशी हिंदुओं के पलायन एवं हत्याओं पर चुप्पी साध लेते हैं। तो क्या यह मान लेना अनुचित है कि भारत में मानवीय संवेदनाओं का राजनीतिकरण हो गया है। किसी भी समाज के लिए यह खतरनाक संकेत है कि उसकी संवेदनाएं पीड़ित की पृष्ठान देखकर जागती हों। यदि अन्याय हुआ है, तो वह अन्याय है-चाहे वह मुसलमान के साथ हो या हिंदू के साथ। जब राजनेता और बुद्धिजीवी केवल एक वर्ग के प्रति सहानुभूति दिखाते हैं, और दूसरे वर्ग की पीड़ा को नजरअंदाज करते हैं, तो वे समाज में अविश्वास की खाई को और चौड़ा करते हैं। किंतु बुद्धिजीवी लोगों को इस रहस्यमई चुप्पी के निहतायँ स्पष्ट समझ में आते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्मों पर भारतीय राजनेताओं की

और सुधार करती रहे। योजना की प्रभावशीलता तभी बनी रहती है जब स्थानीय प्रशासन, पंचायत और लाभार्थियों के बीच संवाद और जवाबदेही हो। यह लोकतांत्रिक शासन की सबसे बड़ी ताकत है।

भरोसे और नीतियों की कसौटी पर 'जी राम जी' बिल ने एक नई मिसाल कायम की है। भविष्य में इसके और भी सफल होने के लिए कुछ कदम आवश्यक हैं।

स्थायित्व और विस्तार: योजना को केवल वर्तमान लाभार्थियों तक सीमित न रखा जाए, बल्कि नई तकनीक और कौशल विकास के साथ इसे बढ़ाया जाए।

पारदर्शिता: सरकारी योजनाओं में लाभार्थियों तक जानकारी, निगरानी और रिपोर्टिंग पारदर्शी हो।

स्थानीय उद्योग और उत्पादन: रोजगार केवल सरकारी कार्यों तक सीमित न हो, बल्कि स्थानीय उद्योग और स्वरोजगार को प्रोत्साहित किया जाए।

महिला और युवा सशक्तिकरण: महिलाओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए ताकि समुदाय आधारित विकास सुनिश्चित हो।

अर्थव्यवस्था और विकास का संतुलन: योजनाओं से केवल रोजगार या राहत न हो, बल्कि स्थायी आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिले।

'जी राम जी' बिल और उससे जुड़ी योजनाएँ यह स्पष्ट करती हैं कि भरोसा और परिणाम राजनीति में दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। केवल घोषणाओं या भाषणों से जनता का विश्वास नहीं बनता। इसे क्रियान्वयन, पारदर्शिता और परिणाम के साथ जोड़ना आवश्यक है।

इस पलटने ने दिखाया कि यदि सरकार योजनाओं को समयबद्ध, प्रभावी और सतत तरीके से लागू करे, तो विश्वास केवल टिकता ही नहीं, बल्कि लोकतंत्र और समाज की मजबूती का प्रतीक बन जाता है।

संक्षेप में, भरोसा केवल राजनीति का जरिया नहीं, बल्कि विकास और सामाजिक न्याय की दिशा में एक स्थायी स्तंभ बन सकता है। 'जी राम जी' बिल इस कसौटी पर खड़ा होता दिख रहा है, और यदि इसे सुधार और सतत निगरानी के साथ आगे बढ़ाया जाए, तो यह भारत के ग्रामीण विकास और लोकतांत्रिक विश्वास का आदर्श मॉडल बन सकता है।

संपादकीय

जानलेवा आबोहवा

देश-दुनिया में दिल्ली में प्रदूषण को लेकर भारी चिंता है, लेकिन यह सिर्फ दिल्ली का ही संकट नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हरियाणा, उ.प्र. व राजस्थान के कई शहर भी प्रदूषणग्रस्त हैं। इसके अलावा लखनऊ, वाराणसी, जयपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, कानपुर व देश के अन्य शहरों में भी प्रदूषण संकट आम लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहा है। हालांकि, इन शहरों में संकट दिल्ली जैसा नहीं है, लेकिन पूरे देश के लिए दीर्घकालीन योजना बनाने की जरूरत तो है। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में तीसरे स्थान पर आने वाली दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक का 450 के आसपास बना रहना, निश्चय ही खतरों की घंटी है। दिल्ली सरकार द्वारा उत्सर्जन मानकों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के शहर में प्रवेश पर रोक, दफ्तरों में वर्क फ्रॉम-होम, स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई, तोड़फोड़ व निर्माण पर रोक के बावजूद आशातीत परिणाम सामने नहीं आए हैं। इसी बीच, चीन के दूतावास ने दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण में मदद की पेशकश की है। चीनी दूतावास की एक प्रवक्ता ने एक्स पर पोस्ट में स्क्रीनशॉट साझा किया है, जिसमें दिल्ली में एक््यूआई 447 व बीजिंग में 67 दिखाई दे रहा है। निस्संदेह, भारत व चीन दोनों ही तीव्र शहरीकरण की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। लेकिन चीन ने योजनाबद्ध ढंग से उस परिदृश्य को दूर किया है, जिसमें चीन के तमाम शहर सर्दियों में स्मॉग से ढके रहते थे। हालांकि, साम्यवादी चीन व लोकतांत्रिक भारत में नीतियों के क्रियान्वयन में मूलभूत अंतर है। फिर भी चीन की सफलता से सीखा जा सकता है। चीन ने पिछले दो दशकों में आक्रामक ढंग से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाया। वाहन उत्सर्जन पर नियंत्रण किया। लाइसेंस प्लेट लाॅटरी व ऑड-ईवन से सड़कों पर वाहनों को कम किया। उसने बड़े मेट्रो-बस नेटवर्क को बढ़ाकर सार्वजनिक परिवहन को मजबूत बनाया। करीब तीन हजार के करीब भारी उद्योगों को बीजिंग व आसपास के शहरों से हटाया गया। एक बड़ी स्टील कंपनी को हटाने से घातक कणों में बीस फीसदी की कमी आई। सबसे अधिक जोर कोयले पर आधारित बिजली संयंत्रों व उद्योगों पर रोक लगाने में लगा। इसके अलावा, निर्माण स्थलों पर धूल-रोधी जाली लगाने, पानी के छिड़काव-स्फाई, किसानों को पराली भत्ता देने व प्रदूषण के पीक समय में निर्माण पर रोक जैसे कदम उठाए। वहां पौधारोपण को बढ़ावा दिया गया। निस्संदेह, बीजिंग व दिल्ली की परिस्थितियाँ अलग हैं, लेकिन बीजिंग मॉडल पर विचार होना चाहिए। दरअसल, दिल्ली की भौगोलिक परिस्थिति बीजिंग से भिन्न है, दिल्ली लैंडलॉकड क्षेत्र है, आसपास समुद्री इलाका भी नहीं है। लेकिन कोयला आधारित संयंत्रों को बंद करने, सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने तथा औद्योगिक संस्थानों को राजधानी की सीमा से बाहर किया जाना चाहिए।

चितन-मनन

धर्म की शरण

हर संसारी प्राणी अपनी सुरक्षा के लिए शरण की खोज करता है। प्राणी उपयुक्त शरण मिलने पर उसे स्वीकार भी कर लेता है। बहिर्दशी व्यक्ति अपने पारिवारिक जनों को शरण मानता है। परिवार के लोग किसी सक्षम सदस्य को शरण मानते हैं। किंतु वे तुम्हें त्राण और शरण देने में समर्थ नहीं हैं और तुम उनको त्राण या शरण देने में समर्थ नहीं हो। यह आम-वाणी मनुष्य को अपनी सही स्थिति का बोध देती है। वह जब चारों ओर से अत्राण और अशरण होकर असहाय हो जाता है, उस समय उसकी अंतमरुखी चेतना में चार प्रकार की शरण आविर्भूत होती है- अर्हत, सिद्ध, साधु और धर्म। ये चार तत्व ऐसे हैं, जो व्यक्ति को शांत शरण दे सकते हैं। इन चारों शरणों में तीन तत्व किसी अपेक्षा से परे भी हो सकते हैं किंतु चौथा तत्व धर्म अपना निजी ही है। इसकी शरण में जाने के लिए कोई अपेक्षा नहीं केवल अपनी वृत्तियों को मोड़ने की जरूरत है।

धर्म क्या है? जो सबको समता और शांति का पाठ पढ़ाए, वह धर्म है। जिस धर्म के सहारे सुख-सुविधा के साधन जुटाए जाते हैं, प्रतिष्ठा की कृत्रिम भूख को शांत किया जाता है, प्रदर्शन और आडंबर को प्रोत्साहन दिया जाता है, उस धर्म की शरण स्वीकार करने से शांति नहीं मिल सकती। ऐसा धर्म समता का सूत्र नहीं दे सकता।

धर्म की कसौटी पर विचार होना चाहिए। दरअसल, दिल्ली की भौगोलिक परिस्थिति बीजिंग से भिन्न है, दिल्ली लैंडलॉकड क्षेत्र है, आसपास समुद्री इलाका भी नहीं है। लेकिन कोयला आधारित संयंत्रों को बंद करने, सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने तथा औद्योगिक संस्थानों को राजधानी की सीमा से बाहर किया जाना चाहिए।

धर्म या स्वभाव- रमण का एक सूत्र है- पदार्थ प्रतिबद्धता का अभाव। कोई व्यक्ति अभाव या अतिभाव के कारण पदार्थ से प्रतिबद्ध नहीं होता है, यह वास्तव में धर्म नहीं है। अभाव में जो व्यक्ति संग्रह नहीं करता, वह त्यागी नहीं होता। इसी प्रकार अतिभाव में पदार्थ का विसर्जन करने वाला भी त्यागी नहीं हो सकता।



योगेश कुमार गोयल

उपभोक्ताओं के विभिन्न हितों और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए देश में प्रतिवर्ष 24 दिसम्बर को ह्वाराष्ट्रीय उपभोक्ता दिवसह मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, उनके हितों के लिए बनाए गए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियमों तथा उनके अंतर्गत आने वाले कानूनों की जानकारी देना है। दरअसल ऑनलाइन खरीददारी हो या ऑफ़लाइन, ग्राहकों को कई बार सामान की गड़बड़ी अथवा अन्य प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इसी तरह की समस्याओं से उन्हें निजात दिलाने तथा उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। हालांकि वर्ष 2020 तक विभिन्न ई-कॉमर्स साइटों से ऑनलाइन खरीददारी को लेकर उपभोक्ताओं को कोई संरक्षण प्राप्त नहीं था लेकिन उपभोक्ता संरक्षण कानून-2019 (कन्स्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट-2019) में ई-कॉमर्स को भी दायरे में लाकर उपभोक्ताओं को और मजबूती देने का प्रयास किया गया। पुराना उपभोक्ता संरक्षण कानून करीब साढ़े तीन दशक पुराना हो चुका था, जिसमें समय के साथ बड़े बदलावों की जरूरत महसूस की जा रही थी। इसीलिए ग्राहकों के साथ अक्सर होने वाली धोखाधड़ी को रोकने और उपभोक्ता अधिकारों को ज्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए 20 जुलाई 2020 को 'उपभोक्ता संरक्षण कानून-2019' (कन्स्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट-2019) लागू किया गया, जिसमें उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की ठगी और धोखाधड़ी से बचाने के लिए कई प्रावधान शामिल हैं।

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस वास्तव में उपभोक्ताओं को



डॉ राघवेंद्र शर्मा

बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की स्थिति और उस पर भारतीय विमर्श में व्याप्त चुनिंदा संवेदनशीलता एक गंभीर और विचारणीय विषय है। बांग्लादेश में दीपचंद की हालिया हत्या और भारतीय गलियायों मेंउसके बाद की राजनीतिक चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। यह भारतीय राजनीति का वह विदूष चहेरा है जो इन विसंगतियों और भेदभावपूर्ण दृष्टिकोणों का विश्लेषण करने की असीमित सामग्री मुहैया कराता है। हाल के दिनों में बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की खबरें विचलित करने वाली रही हैं। दीपचंद की नृशंस हत्या इसी सिलसिले की एक और काली कड़ी है। लेकिन इस घटना से भी अधिक चौंकाने वाली बात है भारतीय राजनीतिक गलियायों में पसरा सनाटा। यह चुप्पी उस समय और भी गहरी लगने लगती है जब हम इसकी तुलना वैश्विक स्तर पर होने वाली अन्य घटनाओं से करते हैं। में व्यक्तिगत तौर पर अनुभव किया है कि मामला हमारे देश के भीतर का हो या फिर सीमा पार का, यदि वहां जुल्म का शिकार कोई हिंदू है तो



यह सुविधाजनक चुप्पी न केवल वहां के अल्पसंख्यकों का मनोबल तोड़ती है, बल्कि कट्टरपंथी ताकतों को भी बढ़ावा देती है। उन्हें लगता है कि उनके कृत्यों का कोई अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक विरोध नहीं होगा। लिखने का आशय यह है कि भारत को अथवा कोई दूसरा देश, मानवाधिकार सार्वभौमिक होने चाहिए, चयनात्मक नहीं। यदि हम गाजा के लिए आवाज उठाते हैं, तो हमें ढाका के दीपचंद के लिए भी उतनी ही मजबूती से बोलना होगा। भारत के राजनेताओं को यह समझना होगा कि तुष्टीकरण की राजनीति अंततः न्याय के सिद्धांतों की हत्या करती है। जब तक मानवता को धर्म के चरम से देखा जाता रहेगा, तब तक दुनिया से अन्याय समाप्त नहीं होगा।

निधि अग्रवाल ने आठ साल में कीं आठ फिल्मों, अब प्रभास संग करेंगी रोमांस

सोशल मीडिया पर अभिनेत्री निधि अग्रवाल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये वायरल वीडियो हैदराबाद में हुए प्रभास और निधि की फिल्म 'द राजा साब' के गाने के लॉन्च इवेंट के बाद का है। निधि इवेंट से निकलकर वापस जा रही थीं, तभी वहां मौजूद भीड़ उन पर इस तरह से टूट पड़ी कि एक्ट्रेस लोगों के बीच में फंस गईं। हालांकि, किसी भी तरह से सिक्वोरिटी गार्ड्स ने निधि को उनकी कार तक पहुंचाया। इस वीडियो के सामने आने के बाद अब लोग भीड़ पर नाराजगी जता रहे हैं।

टाइगर श्रॉफ की फिल्म से एक्टिंग की दुनिया में रखा कदम

साल 2014 में मिस दीवा यूनिवर्स में हिस्सा लेने वाली निधि अग्रवाल ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2017 में की। निधि ने बॉलीवुड की फिल्म 'मुन्ना माइकल' से फिल्मी दुनिया में कदम रखा। टाइगर श्रॉफ स्टारर इस फिल्म के लिए निधि का चयन 300 कैडिडेट के ऑडिशन के बाद हुआ था।

प्रभास के साथ द राजा साब में आएंगी नजर

निधि अग्रवाल अब फिल्म 'राजा साब' में नजर आएंगी। इस हॉरर-कॉमेडी फिल्म को बड़े स्तर पर बनाया गया है। इस फिल्म में निधि अपने से 14 साल बड़े अभिनेता प्रभास के साथ रोमांस फरमाती नजर



आएंगी। 'राजा साब' 9 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। पहले इस फिल्म को 5 दिसंबर को ही रिलीज होना था, लेकिन अब फिल्म अगले साल रिलीज होगी। फिल्म को लेकर काफी बज बना हुआ है। निधि अग्रवाल को इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं।

भीड़ में फंसने के बाद निधि अग्रवाल का वीडियो वायरल है। कई लोग इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और वहां मौजूद लोगों के रवैये पर सवाल उठा रहे हैं। तो वहीं सोशल मीडिया पर कई यूजर्स 'द राजा साब' के मेकर्स पर भी सवाल उठा रहे हैं और उनकी व्यवस्था की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। हालांकि, अभी तक इस पूरे मामले पर निधि अग्रवाल, प्रभास या फिल्म के मेकर्स की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।



सात साल बाद फिर से साथ नजर आने वाले हैं कार्तिक और अनन्या

बॉलीवुड में जब कोई जोड़ी एक बार साथ काम कर चुकी होती है और फिर लंबे समय बाद स्क्रीन पर लौटती है, तो उनके बीच का रिश्ता और काम करने का अनुभव हमेशा चर्चा का विषय बन जाता है। ऐसा ही कुछ कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे के बीच देखने को मिल रहा है। दोनों



फिल्म तू मेरी में तेरा, मैं तेरा तू मेरी में सात साल बाद फिर से साथ नजर आने वाले हैं। 2018 में दोनों ने पहली बार पति, पत्नी और वो में साथ काम किया था, और अब फिल्म की रिलीज से पहले दोनों की कैमिस्ट्री को लेकर काफी बातें हो रही हैं। फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में कार्तिक ने अनन्या के साथ स्क्रीन शेयर करने के अनुभव को साझा किया। कार्तिक ने कहा, मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे अनन्या के साथ काम करने का मौका मिला। उन्होंने फिल्म में शानदार काम किया है और हर सीन में अपने अभिनय का बेहतरीन प्रदर्शन किया है। वह असल में बहुत मेहनती हैं और उनके काम को देखकर सभी को प्रेरणा मिलती है। कार्तिक ने अनन्या के करियर को लेकर कहा, जब अनन्या इंडस्ट्री में आई थीं, तब भी बेहद आत्मविश्वासी थीं और अब एक बेहतरीन अदाकारा बन चुकी हैं। उन्होंने न केवल अभिनय का हुनर दिखाया, बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी खुद को आगे बढ़ाया है। मैंने अनन्या को एक बेहतर इंसान के रूप में बढ़ते हुए देखा है, और यह अनुभव मेरे लिए हमेशा खास रहेगा। उन्होंने बताया कि अनन्या निर्देशक की सलाह को अच्छे से अपनाती हैं और हर सीन में एक नई ऊर्जा लाती हैं।

2018 में तेलुगु और 2021 में तमिल सिनेमा में किया डेब्यू

बॉलीवुड में डेब्यू करने के बाद निधि ने साल 2018 में नागा चैतन्य के साथ फिल्म 'सब्यसाची' से तेलुगु सिनेमा में अपनी शुरुआत की। जबकि साल 2021 में उन्होंने तमिल सिनेमा में अपनी शुरुआत फिल्म 'ईस्वरन' से की। हिंदी फिल्म से अपनी शुरुआत करने वाली निधि अग्रवाल ने अब तक अपने करियर में तीन तेलुगु और दो तमिल फिल्मों में काम किया है। हालांकि, उनके खाते में 'आई स्मार्ट शंकर' को छोड़कर अब तक कोई बड़ी हिट फिल्म नहीं आई है। इस साल वो पवन कल्याण की फिल्म 'हरि हर वीर मल्लू' में भी नजर आई थीं, लेकिन यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई।

इमरान हाशमी ने शुरू की आवारापन 2 की शूटिंग

इमरान हाशमी को हाल ही में फिल्म आवारापन 2 की शूटिंग करते हुए पेट में चोट आई थी। खबरों के मुताबिक एक एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान एक्टर के साथ हादसा हुआ। चोट लगने के बाद उनका इलाज किया गया। अब इमरान हाशमी ने दोबारा फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। इमरान हाशमी को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। उन्हें एक्शन मूवमेंट्स शूट करने की मनाही है। इमरान हाशमी पर फिल्माए जाने वाले एक्शन सीन चोट ठीक हो जाने के बाद फिल्माए जाएंगे। इससे पहले इमरान हाशमी उन सीन्स को शूट करेंगे जो आसान हैं। फिल्म आवारापन 2 इमरान हाशमी की 2007 में आई फिल्म आवारापन का सीकल है। पिछली फिल्म में इमरान हाशमी के साथ श्रेया सरन थीं। इस फिल्म में दिशा पाटनी होंगी।



माधुरी दीक्षित ने अपने करियर, फिल्ममेकिंग में आए बदलाव और फिल्मों के चयन को लेकर बात की

बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री माधुरी दीक्षित चार दशकों से भी ज्यादा समय से फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हैं। उन्होंने न सिर्फ कई सुपरहिट फिल्में दी, बल्कि बदलते दौर के साथ खुद को भी लगातार ढालती रहीं। इस बीच, उन्होंने अपने करियर के सफर, फिल्ममेकिंग में आए बदलाव और आज के समय में फिल्मों के चयन को लेकर बात की। उस दौर को याद करते हुए उन्होंने कहा, तब फिल्म इंडस्ट्री आज जैसी व्यवस्थित नहीं थी। 80 और 90 के दशक में सिर्फ कुछ ही प्रोड्यूसर ऐसे थे, जो काम को बहुत प्रोफेशनल तरीके से करते थे। इनमें यश चोपड़ा, बी. आर. चोपड़ा, सुभाष घई और राजश्री प्रोडक्शन्स जैसे नाम शामिल थे। ज्यादातर फिल्में बिना ज्यादा प्लानिंग और सुविधाओं के बनती थीं। आज की तुलना में उस समय सब कुछ काफी अव्यवस्थित हुआ करता था। माधुरी ने कहा, पहले फिल्मों में काम करते समय कलाकारों को बहुत ज्यादा तैयारी का मौका नहीं मिलता था। शूटिंग अक्सर अचानक शुरू हो जाती थी और कलाकारों को मौके पर ही सीन समझकर शूट करना पड़ता था। आज के समय में स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। अब कलाकारों को पहले से पूरी स्क्रिप्ट

मिल जाती है, किरदार पर विस्तार से काम करने का समय मिलता है और शूटिंग से पहले अच्छी तैयारी की जाती है। इससे कलाकार अपने रोल को बेहतर तरीके से निभा पाते हैं। उन्होंने कहा, पहले शूटिंग के दौरान कलाकारों की सुविधाओं पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। इसके मुकाबले आज फिल्म सेट पर हर सुविधा उपलब्ध होती है। माधुरी ने कहा, आज फिल्मों में किरदारों पर बहुत ज्यादा मेहनत की जाती है। अब यह पहले से तय होता है कि कलाकार क्या पहनेंगे, उनका लुक कैसा होगा, और वे किस तरह से स्क्रीन पर नजर आएंगे। शूटिंग से पहले रीडिंग सेशन और रिवर्सल भी होती है, जो पहले के समय में नहीं हुआ करती थी। इन सब बदलावों से फिल्ममेकिंग का स्तर काफी ऊपर चला गया है।



सख्त पुलिसवाले से लेकर खूंखार गैंगस्टर तक पर्दे पर इन किरदारों से जॉन अब्राहम ने मचाई 'धूम'

मॉडलिंग से अपना करियर शुरू करने वाले जॉन अब्राहम की गिनती इंडस्ट्री के प्रमुख अभिनेताओं में होती है। दो दशक से भी लंबे अपने एक्टिंग करियर में जॉन कई सुपरहिट फिल्मों का हिस्सा रहे हैं। एक्टिंग के अलावा जॉन अब्राहम अपने लुक और बॉडी को लेकर भी अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। अपनी फिल्मों के अलावा उन्होंने कई अन्य सफल फिल्मों का भी निर्माण किया है।

कबीर (धूम)

साल 2004 में आई फिल्म 'धूम' में जॉन अब्राहम ने कबीर नाम के एक चोर की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में जॉन अब्राहम का लुक और बाइक चलाने का उनका स्टेज लोगों को काफी पसंद आया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। इस फिल्म को एक टैंड सेटर फिल्म माना जाता है, जिसने बड़े वालों वाले लुक और बाइक के प्रति लोगों की दीवानगी में इजाफा किया था।

श्याम या सैम (गरम मसाला)

चोर बनकर लोगों का दिल चुराने के बाद जॉन अब्राहम

साल 2005 में आई कॉमेडी फिल्म 'गरम मसाला' में श्याम उर्फ सैम के किरदार में नजर आए थे। इस फिल्म में जॉन अब्राहम अक्षय कुमार के साथ प्रमुख भूमिका में थे। फिल्म में दोनों दोस्त बने हैं। फिल्म में जॉन की कॉमिक टाइमिंग ने सभी को हैरान किया था।

के (नो स्मोकिंग)

अनुराग कश्यप द्वारा निर्देशित फिल्म 'नो स्मोकिंग' भले ही बॉक्स ऑफिस पर सफल न रही हो, लेकिन फिल्म को क्रिटिक्स से काफी सराहना मिली थी। इस फिल्म में जॉन अब्राहम ने के नाम के एक चेन स्मोकर की भूमिका निभाई थी। इस साइकोलॉजिकल थ्रिलर में जॉन अब्राहम के अभिनय की काफी तारीफ हुई थी।

सनी भसीन (गोल)

2007 में आई फिल्म 'गोल' एक स्पोर्ट्स ड्रामा है, जो फुटबॉल पर आधारित है। फिल्म में क्लब फुटबॉल से लेकर नेशनल लेवल तक के फुटबॉल खेल को दिखाया गया है। इस फिल्म में जॉन अब्राहम ने सनी भसीन नाम का किरदार निभाया है, जो एक अच्छा फुटबॉल प्लेयर होता है। जॉन अब्राहम असल जिंदगी में भी काफी अच्छी फुटबॉल खेल लेते हैं।

कुणाल चौहान (दोस्ताना)

फिल्म 'दोस्ताना' दो दोस्तों की कहानी है। फिल्म में जॉन अब्राहम के साथ अभिषेक बच्चन और प्रियंका चोपड़ा प्रमुख भूमिका में नजर आए हैं। फिल्म में सैम (अभिषेक बच्चन) और कुणाल (जॉन अब्राहम) रेंट पर घर लेने के लिए समलैंगिक कपल होने का नाटक करते हैं। इसके बाद लोग उन्हें असल में भी समलैंगिक समझने लगते हैं। फिल्म में जॉन अब्राहम की बॉडी और लुक्स की काफी चर्चा हुई थी। यह फिल्म उनके करियर की अहम फिल्मों में शामिल है।

मान्या सुर्वे (शूटआउट एट वडाला)

संजय गुप्ता द्वारा निर्देशित फिल्म 'शूटआउट एट वडाला' में जॉन अब्राहम ने मान्या सुर्वे का किरदार निभाया है। मान्या 1970-80 के दशक में मुंबई का एक शिक्षित और खूंखार गैंगस्टर रहा है। इस गैंगस्टर के किरदार में जॉन अब्राहम काफी जंचे थे और उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ भी हुई थी।

समीर शेख (न्यूयॉर्क)

कबीर खान की फिल्म 'न्यूयॉर्क' जो 9/11 हमलों के

बाद न्यूयॉर्क में रहने वाले तीन दोस्तों (जॉन अब्राहम, कटरीना कैफ और नील नितिन मुकेश) की कहानी है। फिल्म में जॉन ने समीर शेख उर्फ सैम की भूमिका निभाई है, जो आतंकवाद का गलत आरोप लगाने के बाद आतंकी गतिविधियों में शामिल हो जाता है।

विक्रम सिंह (मद्रास कैफे)

साल 2013 में आई फिल्म 'मद्रास कैफे' सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म है। शूजित सरकार के निर्देशन में बनी इस फिल्म में जॉन अब्राहम ने भारतीय खुफिया जासूस विक्रम सिंह की भूमिका निभाई है। 1980 और 1990 के दशक की शुरुआत में श्रीलंका के गृहयुद्ध और भारतीय हस्तक्षेप से प्रेरित इस फिल्म में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या और उसकी जांच को दिखाया गया है।

एसीपी संजय कुमार (बाटला हाउस)

2018 में दिल्ली के बाटला हाउस में हुए एनकाउंटर पर आधारित फिल्म 'बाटला हाउस' में जॉन अब्राहम ने एसीपी संजय कुमार की भूमिका निभाई है। असल पुलिस वाले के किरदार में जॉन अब्राहम काफी जंचे हैं।

जिम (पठान)

यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की फिल्म 'पठान' में जॉन अब्राहम ने विलेन की भूमिका निभाई है। फिल्म में जॉन ने जिम नाम के पूर्व रॉ एजेंट और आउटफिट एक्स नाम के आतंकी संगठन के सरगना का किरदार निभाया है। शाहरुख खान स्टारर इस फिल्म में जॉन एक खूंखार, शक्तिशाली और दहशत फैलाने वाले विलेन के किरदार में नजर आए हैं।

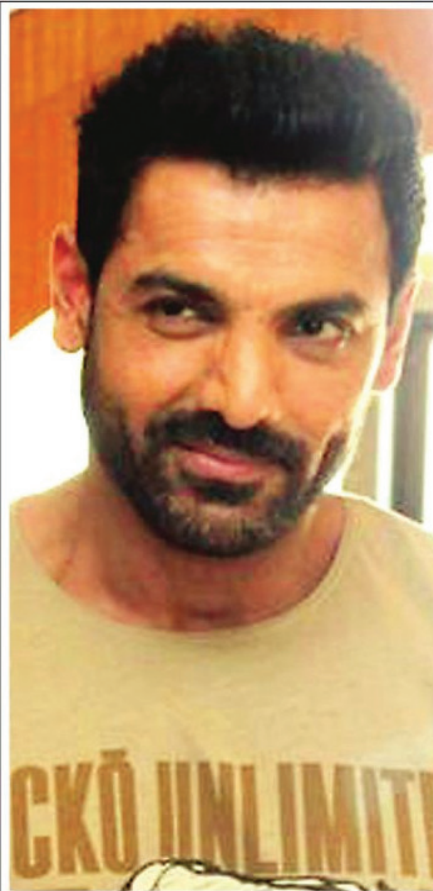


60 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में शिल्पा शेटी ने तोड़ी चुप्पी

बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेटी और उनके पति-बिजनेसमैन राज कुंद्रा इन दिनों कानूनी विवादों में हैं। दरअसल, उनका नाम 60 करोड़ रुपये के कथित धोखाधड़ी और ठगी केस से जुड़ा है। उन्होंने खुद पर लगे सभी आरोपों को सिर से खारिज किया। अब शिल्पा शेटी ने भी इस पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में उनका नाम गलत तरीके से लिया गया है। उन्होंने कहा कि संबंधित कंपनी में उनकी भूमिका सीमित और गैर-ऑपरेशनल थी। शिल्पा शेटी की टीम की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है, इस मामले से मेरा नाम जोड़ने की बेवुनियाद कोशिश से मुझे बहुत दुख हुआ है। कंपनी के साथ मेरा जुड़ाव पूरी तरह से नॉन-एजजीक्यूटिव था, जिसमें ऑपरेशंस, फाइनेंस, फैसले लेने या किसी भी साइनिंग अथॉरिटी में मेरी कोई भूमिका नहीं थी। असल में, कई दूसरी जानी-मानी हस्तियों की तरह मैंने भी होम शॉपिंग चैनल के लिए कुछ प्रोडक्ट्स को प्रोफेशनल तौर पर एंडोर्स किया था, जिसके लिए मुझे मिलने वाला पेमेंट अभी भी बकाया है। जारी बयान में कहा गया है कि कंपनी के रोजाना के कामकाज, फाइनेंस या फैसले लेने में उनकी (शिल्पा शेटी) कोई भूमिका नहीं थी।

कंपनी को करोड़ों का लोन देने की कही बात

शिल्पा शेटी ने आगे आरोप लगाया कि उनके परिवार ने कंपनी को एक बड़ी रकम लोन के तौर पर दी थी, जिसमें लगभग 20 करोड़ रुपये का लोन दिया गया था और वह रकम अभी भी चुकाई नहीं गई है। एक्ट्रेस ने हा, मैं यह रिकॉर्ड पर लाना चाहती हूँ कि हमारे परिवार ने कंपनी को लगभग 20 करोड़ रुपये का लोन दिया है और वह रकम अभी भी बकाया है। मुझ पर आपराधिक जिम्मेदारी डालने की यह कोशिश, खासकर लगभग नौ साल की बिना किसी वजह की देरी के बाद, कानूनी तौर पर गलत है और कानून के तय सिद्धांतों के खिलाफ है। बोली- न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा है एक्ट्रेस ने आगे कहा, इन तथ्यों के बावजूद, मेरा नाम बेवजह कार्यवाही में घसीटा जा रहा है, जो परेशान करने वाला और गलत है। ऐसे बेवुनियाद आरोप न केवल तथ्यों को गलत तरीके से पेश करते हैं, बल्कि सार्वजनिक तौर पर एक महिला की गरिमा, ईमानदारी और प्रतिष्ठा को भी गलत तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। बयान में आगे कहा गया, बॉम्बे हाई कोर्ट में पहले ही एक याचिका दायर की जा चुकी है, मुझे न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है और मैं अपने अधिकारों और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए उचित कानूनी उपाय करूंगी।





कितना सही है नाश्ते में दही लेना

नाश्ते में हम सभी कुछ ऐसा खाना पसंद करते हैं, जो खाने में टेस्टी हो और हमारे शरीर को पूरा दिन काम करने की एनर्जी देता रहे। ऐसे में ज्यादातर लोग किसी ना किसी रूप में नाश्ते में दही खाना पसंद करते हैं। लेकिन क्या नाश्ते में दही लेना एक स्वस्थ विकल्प है?

पाचक होती है लेकिन नींद दिलाती है

- यदि आपके दिन शुरुआत ही दही के साथ हो रही है तो यह आपको एनर्जी देने के स्थान पर नींद दिला सकती है और शरीर में सुस्ती बढ़ा सकती है। इसलिए दही कभी भी आपके फर्स्ट फूड का भाग नहीं होना चाहिए। हालांकि दही नाश्ते का एक शानदार हिस्सा है। यदि आप इसे खाते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखते हैं तब,

समझे विरोधी बातों का अर्थ

- एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि दही नाश्ते में खाना अच्छा है। वहीं दूसरी तरफ यह भी कह रहे हैं कि इसे खाने से सुस्ती बढ़ सकती है। दरअसल, ये दोनों ही बातें सही हैं। दही खाने पर आपको एनर्जी मिलेगी या सुस्ती आएगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि दही खाने का आपका तरीका क्या है।

इस तरह खाएं और इस तरह ना खाएं दही

- आप नाश्ते में चपाती, पराठा, चिल्ला आदि के साथ दही खा सकते हैं। एक कटोरी दही का सेवन नाश्ते में करना शरीर के लाभकारी होता है और पाचनतंत्र को सही करता है। साथ ही शरीर को दिनभर के लिए ऊर्जा देने में लाभकारी होता है।
- लेकिन नाश्ते में दही का सेवन तभी करना चाहिए जब आप सुबह के समय नाश्ते से पहले कुछ खा या पी चुके हो। जैसे, सुबह की शुरुआत आपने पानी के साथ को हो और फिर चाय-टोस्ट, स्पाउट्स या ड्राईफ्रूट्स आदि खाएं। इसके एक घंटे बाद यदि आप नाश्ते में दही का सेवन करते हैं तो आपको नींद नहीं आएगी। आपको गैस बनने की समस्या है तो इन 5 सब्जियों से बचना चाहिए

खाली पेट नहीं खानी चाहिए दही

- सुबह के समय आप नाश्ते में केवल मीठी दही का उपयोग कर सकते हैं। खट्टी दही खाने से परहेज करें। साथ ही नाश्ते में दही खाते समय आप इसमें एक चम्मच शक्कर मिला सकते हैं। यदि आपको शुगर की समस्या नहीं है तब।
- दिन की शुरुआत यदि किसी भी कारण देरी से हुई हो और आपके पास नाश्ता करने का समय ना हो तो भूलकर भी खाली दही ना खाएं। यदि आप खाली पेट दही खाते हैं तो आपको जबदस्त नींद आएगी और आप खुद को बहुत थका हुआ अनुभव करेंगे।
- ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खाली पेट दही खाने से कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर कम होने की समस्या हो जाती है। इससे शरीर में ब्लड का प्लो कम होता है और ऑक्सीजन का स्तर घटने लगता है। यही कारण है कि बहुत तेज नींद आती है और बेहोशी जैसा अनुभव होता है।



आप चाहे मानसिक काम अधिक करते हैं या शारीरिक काम। यदि आपको काम करते समय बहुत जल्दी थकान होने लगती है तो इसका एक अर्थ यह होता है कि आपके शरीर में डिहाइड्रेशन की समस्या है। जी हां, केवल पोषण की कमी के कारण ही नहीं बल्कि शरीर में पानी की कमी के कारण भी जल्दी थकान होती है। जो लोग नियमित रूप से जरूरी पानी नहीं पीते हैं, उन्हें काम करते समय अधिक थकान होना और अन्य लोगों की तुलना में जल्दी थकान होने जैसी समस्याएं होती हैं। जानें, जल्दी थकान होने के अन्य कारण और उनके निवारण के तरीके

जल्दी थकने की वजह

- आमतौर पर जो लोग बहुत जल्दी थकान होने की समस्या से पीड़ित होते हैं, उनके शरीर में कुछ खास तत्वों की कमी देखने को मिलती है,
- पानी की कमी
- खून की कमी
- विटमिन - बी12 की कमी
- फोलेट या फॉलिक एसिड की कमी देखने को मिलती है।

जल्दी थकान से बचने के तरीकों में ना केवल अपने खान-पान पर ध्यान देना है बल्कि यह भी ध्यान देना है कि जिस डाइट का सेवन आप कर रहे हैं और जिन ड्रिंक्स को आप ले रहे हैं, क्या वे आपके शरीर की जरूरतों को पूरा कर रही हैं। यहां जानें कैसे रखा जाएगा इस बात का ध्यान,

तरल पदार्थों का सेवन

- जल्दी-जल्दी होने वाली थकान की समस्या से बचने के लिए जरूरी है कि आप तरल पदार्थों का सेवन बढ़ा दें। इनमें जूस, सूप, छाछ, दाल इत्यादि शामिल हैं। इसके साथ ही समय-समय सादा पानी पीते रहें। वयस्कों को हर दिन कम से कम 8 गिलास पानी पीना चाहिए।

तनाव को नियंत्रित करना सीखें

- जल्दी थकने की एक बड़ी वजह लगातार बना रहनेवाला तनाव भी होता है। तनाव का कारण चाहे जो भी लेकिन यह व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से जल्द थका देता है। इसलिए तनाव से



बचने के लिए हर दिन कुछ समय के लिए मेडिटेशन यानी ध्यान जरूर करें। यह आपको मानसिक रूप से फिट रखने का काम करेगा।

फलियों का सेवन करें

- हरी फलियां कई तरह की वरायटी में आती हैं। खास बात यह है कि मौसम की प्रकृति और उस दौरान शरीर की जरूरत के अनुसार हर सीजन में आनेवाली फलियां पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं।



चैन की नींद सोना है तो जरूर करें यह काम

अगर आप चाहते हैं कि रात में आपको सुकून की नींद आए, पैरों में कुलन और बेवैनी के कारण आपकी नींद में किसी तरह की बाधा ना आए तो आपको सोने से पहले एक खास काम करना होगा। यह काम आपके शरीर को राहत देने के साथ ही दिमाग को भी शांति देगा। आइए, जानते हैं कि आखिर क्या और कैसे करना है.

आपको क्या करना है ?

- बिस्तर पर जाने से पहले आपको अपने पैर साफ पानी से धुलकर कॉटन के कपड़े से पोछकर साफ करने हैं। इसके बाद सरसों के तेल से अपने पैरों की मालिश करें। यह मालिश 2 से 3 मिनट की भी हो तो काफी है। यहां जानें इस तरह हर दिन मालिश करने से आपको किस तरह के लाभ होंगे.

पैर के तलुए में होते हैं सभी एक्युप्रेशर पॉइंट्स

- हमारे पैर के तलुओं में पूरे शरीर के एक्युप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। पैर के तलुओं पर मसाज करने से इन पॉइंट्स पर दबाव पड़ता है, जिससे शरीर का तनाव कम होता है और मानसिक शांति बढ़ती है। इसलिए आप अच्छी नींद आती है।

ताउम्र रहेंगे युवा

- अगर आप हर दिन सोने से पहले अपने पैर के तलुओं पर सरसों के तेल से मालिश करेंगे तो आप ताउम्र युवा बने रहेंगे। यहां युवा बने रहने से हमारा आशय है कि आपके दांत, आपकी दृष्टि और आपके शरीर के जोड़ों में किसी तरह का दर्द या समस्या नहीं हो पाएगी।

चश्मा नहीं लगेगा

- यदि आप सोने से पहले हर दिन अपने पैरों पर सरसों तेल से मालिश करते हैं तो आप अपनी कमजोर आइसाइट को भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको एक या दो हफ्ते में ही इसका असर देखने को मिल जाएगा।

पाचन को ठीक रखे

- आपको जानकर थोड़ी हैरानी हो सकती है। लेकिन यह सही है कि जो लोग नियमित रूप से अपने पैर के तलुओं पर मालिश करते हैं या किसी और से कराते हैं, उनका पाचनतंत्र अन्य लोगों की तुलना में काफी ठीक रहता है। साथ ही उन्हें पेट संबंधी रोग नहीं घेरते हैं।
- साथ ही ऐसे लोगों के शरीर पर थकान हावी नहीं हो पाती है। पैर के तलुओं की मसाज करने से शरीर के डैमेज सेल यानी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की जल्द मरम्मत होती है। इससे त्वचा भी चमकदार बनी रहती है। तो देर किस बात की, खूबसूरती और सेहत के लिए आज से ही शुरू करें पैर के तलुओं की मालिश।



शरीर में ऑक्सीजन की कमी के लक्षण और कारण

शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाना कई रोगों का कारण बनता है। ऑक्सीजन का स्तर कम होने पर सबसे जल्दी और सबसे बुरा असर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर पड़ता है। इस स्थिति में कोई भी वायरस और बैक्टीरिया हमारे शरीर पर हावी हो सकता है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी के लक्षण और कारण क्या होते हैं.

शरीर में ऑक्सीजन की कमी के लक्षण

- शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने से अर्थ है कि शरीर को अपनी नियमित क्रियाओं को सुचारु रूप से चलाने के लिए जितनी मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए, उतनी मात्रा में ऑक्सीजन ना मिल पाना।
- जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है तो सबसे पहले व्यक्ति को थकान महसूस होती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती या सांस फूलने लगता है। इसके बाद शरीर में रक्त के प्रवाह की गति धीमी हो जाती है। इससे थकान और घबराहट बढ़ जाती है।

हो सकती हैं ये बीमारियां

- यदि शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाए तो ब्रेन डैमेज और हार्ट अटैक तक की स्थिति बन जाती है। शुगर के रोगियों में यदि ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो उनकी शुगर अचानक बहुत अधिक बढ़ सकती है, जो कि एक जानलेवा स्थिति भी बन सकती है।
- ऑक्सीजन का स्तर अचानक से बहुत अधिक घट जाने पर शरीर में थायरॉइड हॉर्मोन का संतुलन गड़बड़ा जाता है। इस स्थिति में थायरॉइड का स्तर या तो बहुत अधिक बढ़ सकता है या बहुत अधिक घट सकता है।

शरीर में ऑक्सीजन की कमी के कारण

- शरीर में ऑक्सीजन की कमी के कई कारण होते हैं, जो व्यक्ति की लाइफस्टाइल पर निर्भर करते हैं। जो लोग बहुत अधिक आलस से भरपूर जीवनशैली जीते हैं यानी फिजिकल ऐक्टिविटी नहीं करते हैं, उनके शरीर में भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है।
- जो लोग बहुत अधिक शारीरिक श्रम करते हैं लेकिन उसके हिसाब से डाइट नहीं लेते हैं, उनके शरीर में भी ऑक्सीजन की कमी हो सकती है।
- जिन लोगों के भोजन में आयरन की मात्रा कम होती है अगर वे लंबे समय तक इसी तरह का भोजन लेते रहें तो उनके शरीर में भी ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। क्योंकि फेफड़ों सहित पूरे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह करने में आयरन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।



आंखें शरीर का सबसे जरूरी, सुंदर और नाजुक अंग है। सर्दी के मौसम में नमी और ठंडक के कारण आंखों में पानी आ जाता है लेकिन यह ड्राई आई सिंड्रोम का संकेत भी हो सकता है। इस बीमारी में आंखों से बहुत ज्यादा पानी आना, धुंधला दिखाई देना और चुभन महसूस होना, सूजन, रैशेज, लालपन जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इस बीमारी का समय पर इलाज न करने पर आंखों की रोशनी जा भी सकती है। ऐसे में इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप डॉक्टर की दवाइ के साथ-साथ कुछ घरेलू उपाय भी कर सकते हैं। इन घरेलू नुस्खों की मदद से आप बिना किसी नुकसान के इस परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं।

गौला कपड़ा - आंखों को हाथों से इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। आंखों में जलन, दर्द या खुजली होने पर साफ पानी में कपड़े को भिगोकर आंखों की सफाई करें। इससे किसी भी तरह की बीमारी का खतरा कम हो जाता है।

नारियल का तेल - नारियल तेल में मौजूद गुण आंखों की गंदगी को साफ करते हैं। रोजाना आंखों के नीचे और आस-पास नारियल के तेल की मालिश करें। आपको इस समस्या से निजात मिल जाएगा।

हर्बल टी - कोमोमाइल या पेपरमिट चाय की पतियों को थोड़ी देर गर्म पानी में भिगो दें। इसके बाद थोड़ी-थोड़ी देर में आंखों की सिकाई करें। ध्यान रहे कि पानी ज्यादा गर्म न हो।

नमक - कई बार आंखों में जलन और खुजली के कारण पानी आने लगता है। ऐसे में आप 1 गिलास गर्म पानी में

ड्राई आई सिंड्रोम का संकेत हो सकता है आंखों में पानी आना

चूटकीभर नमक डालकर आंखों की सिकाई करें। दिन में 3 बार इसका इस्तेमाल खुजली और जलन की परेशानी को दूर कर देगा।
बेकिंग सोडा - साफ पानी में 1 चम्मच बेकिंग सोडा मिलाकर गर्म करें। पानी थोड़ा रह जाने पर इससे अपनी आंखों को धो लें। इससे आपको आराम मिल जाएगा।
दंडा दूध - कॉटन बॉल को ठंडे दूध में डिप करके अपनी आंखों के आस-पास रगड़ें। इसके अलावा आप कॉटन बॉल को ठंडे दूध में भिगोकर रख भी सकते हैं। इन उपायों को सुबह-शाम करने से आपको आराम मिल जाएगा।
एलोवेरा - एलोवेरा जेल में 1 चम्मच शहद और 1/2 कप एल्डरबैरी चाय मिलाएं। रोजाना दिन में 2 बार इस मिश्रण से अपनी आंखों को धोएं। आपकी परेशानी कुछ समय में ही दूर हो जाएगी।
कच्चा आलू - एस्ट्रिजेंट के गुणों से भरपूर कच्चा आलू आंखों में पानी आने की समस्या से जल्दी राहत देता है। आलू की पतली स्लाइस काट कर कुछ देर फ्रिज में रखें। इसके बाद इस ठंडी स्लाइस को 15 से 20 मिनट के लिए आंखों के उपर रख लें। 2-3 दिन तक इसका इस्तेमाल आपकी इस समस्या को दूर कर देगा।

जनसेवा को समर्पित एम्बुलेंस का नवोदित वंशाचार्य पंथ श्री उदितमुनि नाम साहेब ने किया शुभारंभ

पंडरिया। आज पंथ श्री 108 हुजूर उग्रनाम साहेब स्मृति संत समामग मेला, लोलेसरा में संत शिरोमणि कबीर साहेब जी की तपोभूमि, कबीर आश्रम दामाखेड़ा के नवोदित वंशाचार्य पंथ श्री उदितमुनि नाम साहेब जी से पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने सौजन्य भेंट कर आश्रम द्वारा संचालित पंथ श्री गुन्धमुनि नाम साहेब मेमोरियल हॉस्पिटल, दामाखेड़ा में आपातकालीन समय में जरूरतमंद लोगों की सहायता और सेवा के लिए एक एम्बुलेंस समर्पित किया। इस अवसर पर नवोदित वंशाचार्य पंथ श्री उदितमुनि नाम साहेब जी के करकमलों से हरी झंडी दिखाकर जनसेवा हेतु समर्पित एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया गया और भावना बोहरा ने उनसे विभिन्न सामाजिक विषयों पर चर्चा की। इस अवसर पर दामाखेड़ा आश्रम के नवोदित वंशाचार्य पंथ श्री उदितमुनि नाम साहेब जी ने विधायक भावना बोहरा के इस सेवा भाव एवं प्रकल्प की

सराहना की। उन्होंने कहा कि पंडरिया विधायक भावना बोहरा द्वारा जरूरतमंद लोगों की सेवा हेतु समर्पित यह एम्बुलेंस केवल एक वाहन नहीं, बल्कि मानव सेवा, करुणा और उनकी संवेदनशीलता का सजीव प्रतीक है। अपने नाम के अनुरूप हर व्यक्ति, वर्ग और समाज के लिए उनकी सेवा भावना एक सच्चे जनप्रतिनिधि की पहचान है। दामाखेड़ा आश्रम के प्रमुख परम पूज्य पंथ श्री हुजुर प्रकाशमुनी नाम साहेब जी ने भी भावना बोहरा द्वारा जनसेवा हेतु इस एम्बुलेंस के लिए उनकी सराहना की। इस दौरान उन्होंने मंत्री श्री दयाल दास बघेल जी भी साथ में उपस्थित रहे।

इस अवसर पर पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने कहा कि सद्भाव,भक्ति और सामाजिक सद्धारण के प्रतीक परम पूज्य कबीर साहेब जी ने अपने वचनों में मानवता, समानता और सेवा को सर्वोच्च स्थान दिया है। उनके उन्हीं मूल्यों से प्रेरित होकर हमने यह



एम्बुलेंस जनता की सेवा हेतु समर्पित किया है जो आश्रम परिसर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आवश्यकता के समय यह एम्बुलेंस जीवनरक्षक सिद्ध होगी और जरूरतमंदों के लिए आशा की किरण बनेगी। क्षेत्र की जनसमस्याओं के समाधान, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और आमजन के जीवन स्तर को बेहतर बनाने हेतु हम प्रतिबद्ध हैं। आज संत समामग मेला के अवसर पर उपस्थित होकर

प्रयास कर रहें हैं। नवोदित वंशाचार्य पंथ श्री उदितमुनि नाम साहेब जी द्वारा भी कबीर साहेब जी के वचनों को युवाओं तक पहुंचाने और उन्हें अपनी संस्कृति,सभ्यता और सामाजिक एकता के लिए प्रेरित कर रहें हैं।

उन्होंने आगे कहा कि हम सभी भली-भांति जानते हैं कि आपातकालीन परिस्थितियों में समय पर चिकित्सा सुविधा मिलना कितना आवश्यक होता है। दामाखेड़ा आश्रम द्वारा संचालित पंथ श्री गुन्धमुनि नाम साहेब मेमोरियल हॉस्पिटल भी जनसेवा के लिए निरंतर कार्य कर रही है। जरूरतमंदों की सहायता के लिए यह अस्पताल महत्वपूर्ण सेवा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों तक पहुंचा रही है जिससे उन्हें मानसिक व आर्थिक सहयोग मिल रहा है और इन प्रयासों के लिए जितनी सराहना की जाए वह कम है। परम पूज्य पंथ श्री हुजुर प्रकाशमुनी नाम साहेब जी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन मुझे हमेशा

मिलता रह अहै जिसने मुझे भी एक नई दिशा एवं अपने कर्तव्यों के प्रति हमेशा प्रेरित और मार्ग प्रशस्त किया है। ऐसे में समाज सेवा के लिए उनके प्रयास में हमने भी अपनी एक छोटी सी भागीदारी निभाने का अवसर मिला है। इस एम्बुलेंस के माध्यम से आश्रम परिसर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के जरूरतमंदों को त्वरित स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध हो सकेगी। मेरा विश्वास है कि यह सेवा आनेकी जीवनों की रक्षा करेगी और आपातकालीन परिस्थिति में जरूरतमंद लोगों के लिए संबल बनेगी।

भावना बोहरा ने कहा कि मेरे लिए जनप्रतिनिधि होने का अर्थ केवल दायित्व नहीं, बल्कि सेवा का अवसर है। जनता का विश्वास और आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारा निरंतर प्रयास रहा है और आगे भी रहेगा।

कटघोरा में भाजपा नेता अक्षय गर्ग

हत्याकांड मामले : 5 संदिग्ध हिरासत में,

जल्द होगा खुलासा

कोरबा। जिले के कटघोरा थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक कंस्ट्रक्शन साइट पर भाजपा नेता अक्षय गर्ग की धारदार हथियार से नृशंस हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस सनसनीखेज हत्याकांड में पुलिस ने अब तक 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार पुलिस जल्द ही पूरे मामले को खुलासा कर सकती है। मंगलवार सुबह हुई इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है। भाजपा नेता और पीएमजीएसवाई ठेकेदार अक्षय गर्ग की हत्या की खबर मिलते ही पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गया। पुलिस ने घटनास्थल से अहम सुराग जुटाते हुए संभावित आरोपियों को पकड़कर पूछताछ तेज कर दी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हत्या के पीछे पुरानी रंजिश सामने आ रही है। वारदात में इस्तेमाल किया गया।

सरस्वती शिशु मंदिर हाई स्कूल, आमदी में आयोजित हुआ सप्त शक्ति संगम कार्यक्रम

मुख्य अतिथि के रूप में शामिल

हुई भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष रंजना

धमतरी। सरस्वती शिशु मंदिर हाई स्कूल, आमदी में विद्याभारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के अंतर्गत सप्त शक्ति संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं धमतरी की पूर्व विधायक श्रीमती रंजना डीरेंद्र साहू की विशेष उपस्थिति रही।

कार्यक्रम में नगर पंचायत आमदी की अध्यक्ष श्रीमती ज्योति साहू, भाजपा वरिष्ठ नेत्री बिधीका शर्मा, पार्षद चंद्रकाश जी साहू, शिक्षिका शोभा दुबे, प्रधानाचार्य जनक साहू, सरस्वती शिशु मंदिर अध्यक्ष तेजराम साहू, उपाध्यक्ष हेमंत माला, शिक्षिका उर्मिला साहू, लक्ष्मी साहू, भुनेश्वरी साहू, मधु साहू, प्रमिला साहू सहित अन्य अतिथि, मातृशक्तियां, शिक्षकगण एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी

उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां भारती एवं मां सरस्वती की पूजा अर्चना से आरंभ हुआ, कार्यक्रम के दौरान पंच परिवर्तन के अंतर्गत कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समस्यासत, स्व का बोध, पर्यावरण संरक्षण एवं नागरिक कर्तव्य जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अतिथियों द्वारा विस्तार से विचार रखे गए।

इन विषयों के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का संदेश दिया गया। मुख्य अतिथि श्रीमती रंजना डीरेंद्र साहू ने कहा कि नारी शक्ति समाज की आधारशिला है, जब महिलाएं नेत्री बिधीका शर्मा, पार्षद चंद्रकाश जी साहू, शिक्षिका शोभा दुबे, प्रधानाचार्य जनक साहू, सरस्वती शिशु मंदिर अध्यक्ष तेजराम साहू, उपाध्यक्ष हेमंत माला, शिक्षिका उर्मिला साहू, लक्ष्मी साहू, भुनेश्वरी साहू, मधु साहू, प्रमिला साहू सहित अन्य अतिथि, मातृशक्तियां, संस्कारवान और जिम्मेदार बनाने का कार्य करते हैं।

शासन की योजनाओं ने बदली तकदीर, मछली पालन बना स्थायी आय का जरिया

रायपुर। राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं अब कारगजों से निकलकर जमीन पर असर दिखा रही हैं। खासतौर पर मत्स्य पालन को बढ़ावा देने वाली योजनाओं ने ग्रामीण इलाकों में स्वरोजगार के नए रास्ते खोले हैं। इन योजनाओं से जुड़कर किसान न सिर्फ अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं, बल्कि आत्मनिर्भर जीवन की ओर भी कदम बढ़ा रहे हैं। ऐसी ही एक मिसाल बलरामपुर–रामानुजगढ़ जिले के ग्राम हरिंगवा के किसान मुन्नालाल गोलदार हैं। बाड़फ्फनगर विकासखंड के हरिंगवा गांव निवासी मुन्नालाल गोलदार पहले पारंपरिक खेती पर निर्भर थे, जिससे सीमित आमदनी हो पाती थी। लेकिन जब उन्होंने मत्स्य विभाग के मार्गदर्शन में शासन की योजनाओं का लाभ



लिया, तो उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल गई। उन्होंने हरिंगवा जलाशय को पट्टे पर लेकर मछली पालन की शुरुआत की और सघन मत्स्य पालन तकनीक को अपनाया।

मुन्नालाल ने रोहू, कतला, मृगाल और कॉमन कार्प जैसी उन्नत मछली प्रजातियों का पालन किया। बेहतर प्रबंधन, नियमित देखरेख और आधुनिक तकनीक

के उपयोग का नतीजा यह हुआ कि आज उन्हें मछली पालन से हर साल करीब 2 लाख रुपये का शुद्ध मुनाफ़ हो रहा है। इस काम में उनके परिवार के सदस्य भी सहयोग कर रहे हैं, जिससे परिवार को रोजगार का स्थायी साधन मिला है। मुन्नालाल बताते हैं कि स्थानीय बाज़ार में मछलियों की मांग हमेशा बरती रहती है, इसलिए बिक्री में कोई दिक्कत नहीं आती।

मछली पालन से मिलने वाली स्थायी आमदनी ने उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाया है। अब वे भविष्य में आय के और साधन जोड़ने की योजना बना रहे हैं। उनका कहना है कि वे तालाब के पास कुकूट शेड लगाकर मछली पालन के साथ-साथ मुर्गी पालन भी शुरू करना चाहते हैं।

धर्मांतरण के विरोध में भानुप्रतापपुर रहा पूर्णतः बंद, सड़कों पर दिखा आक्रोश

भानुप्रतापपुर। ईसाई मिशनरियों द्वारा कथित तौर पर किए जा रहे जबर्न धर्मांतरण के खिलाफआहतु' छत्तीसगढ़ बंद' का भानुप्रतापपुर में व्यापक और ऐतिहासिक असर देखने को मिला। नगर के व्यापारियों और आम जनमानस ने एकजुटता दिखाते हुए अपने प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रखे, जिससे सुबह से ही बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। इस बंद को किसी एक वर्ग का नहीं, बल्कि सर्व समाज का व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ। सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों और स्थानीय नागरिकों ने सड़कों पर उतरकर शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों का स्पष्ट कहना था कि क्षेत्र की भोली-भाली जनता और विशेषकर आदिवासी समाज की धार्मिक आस्था व परंपराओं के साथ मिशनरियों द्वारा सुनियोजित तरीके से छेड़छाड़ की जा रही है। आक्रोशित लोगों ने आरोप लगाया कि प्रलोभन और अन्य माध्यमों से किया जा रहा धर्मांतरण सामाजिक ताने-बाने को बिगाड़ रहा है। समाज प्रमुखों ने चेतावनी दी कि यदि इन गतिविधियों पर तत्काल रोक नहीं लगाई गई, तो आने वाले समय में आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। हमारी धार्मिक आस्था और आदिवासी संस्कृति के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह बंद प्रशासन को एक कड़ी चेतावनी है।

जिले में दो दिवसीय प्रशिक्षण से स्व-सहायता समूह सदस्यों को मिला उत्पादन से विपणन तक का व्यावहारिक ज्ञान

स्व-सहायता समूहों को बाजार से जोड़ने की दिशा में ठोस पहल

धमतरी। धमतरी जिले के स्व-सहायता समूहों का आर्थिक रूप से सशक्त बनाने तथा उनके उत्पादों को व्यापक बाजार से जोड़ने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा एक सराहनीय पहल की गई। कलेक्टर श्री अंबिनारा मिश्रा के मार्गदर्शन एवं निर्देश पर ऋष्ट संस्था के सहयोग से दो दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल आयोजन नगर निगम के सामुदायिक

भवन में किया गया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य स्व-सहायता समूहों को पारंपरिक उत्पादन से आगे बढ़कर संगठित, ब्रांडेड एवं बाजार-उन्मुख उद्यमों के रूप में विकसित करना रहा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले के सभी विकासखंडों से चयनित 40 स्व-सहायता समूह सदस्यों ने सक्रिय सहभागिता की। प्रतिभागियों को उनके द्वारा निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता सुधार, मानकीकरण, आवर्षक पैकेजिंग, प्रभावी ब्रांडिंग तथा विपणन रणनीतियों की व्यवहारिक जानकारी प्रदान की

गई। कार्यक्रम के दौरान यह समझ विकसित की गई कि गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के साथ-साथ सही प्रस्तुति और बाजार की मांग के अनुरूप रणनीति अपनाने से उत्पादों की बिक्री और मूल्य दोनों में वृद्धि संभव है।

इस अवसर पर जिला कार्यक्रम प्रबंधक (आजीविका) श्री अनुराग मिश्रा ने समूह सदस्यों को उद्यम आधार पंजीयन, स्रस्त्रु पंजीयन, गुणवत्ता मानक, विधिक प्रक्रियाएं, मूल्य निर्धारण, लागत विश्लेषण तथा बाजार से सीधा जुड़ाव जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार

से मार्गदर्शन दिया। उन्होंने बताया कि आवश्यक पंजीकरण एवं मानकों का पालन करने से स्व-सहायता समूहों के उत्पाद न केवल स्थानीय बल्कि राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के बाजारों तक भी पहुंच बना सकते हैं। इससे समूह सदस्यों की आय में स्थायी वृद्धि के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। संस्था के विशेषज्ञों द्वारा ब्रांड निर्माण, उपभोक्ता व्यवहार की समझ, बाजार लिंकेज, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया के माध्यम से उत्पाद प्रचार तथा बाजार-उन्मुख उत्पादन

रणनीतियों पर आधारित व्यावहारिक सत्र आयोजित किए गए। प्रशिक्षण के दौरान समूह सदस्यों को वास्तविक उदाहरणों के माध्यम से यह बताया गया कि किस प्रकार छोटे स्तर से शुरू कर उत्पादों को बड़े बाजार तक पहुंचाया जा सकता है।

प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण को अत्यंत उपयोगी बताया हुए कहा कि इससे उन्हें अपने उत्पादों को अधिक पेशेवर ढंग से प्रस्तुत करने, ब्रांड पहचान विकसित करने तथा नए बाजारों तक पहुंच बनाने की स्पष्ट दिशा मिली है।

संक्षिप्त-खबर

केरल माॅब लिचिंग पीड़ित का अंतिम संस्कार, गांव में पसरा मातम

सक्ती । केरल में कथित माॅब लिचिंग की घटना में जान गंवाने वाले रामनारायण बघेल का पार्थिव शरीर उनके गृह ग्राम करही पहुंचते ही पूरे इलाके में शोक का माहौल बन गया। शव के गांव पहुंचने पर हर आंख नम दिखी और प्रजनों का रो-रोकर बुरा हाल रहा।

अंतिम यात्रा में सक्ती स्‍ट्रु तहसीलदार, जनप्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। पूरे गांव में गमगीन माहौल रहा। करही स्थित मुक्तिधाम में पूरे विधि-विधान के साथ मृतक का अंतिम संस्कार किया गया। इस मामले में केरल प्रशासन ने पीड़ित परिवार की मांगों पर संवेदनशील रख अपनाया है। घटना को लेकर आरोपियों पर माॅब लिचिंग और स्‍ट-स्‍क्र एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। पूरे प्रकरण की जांच के लिए स्‍ट्रुज्ज का गठन किया गया है।

वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। परिजनों ने सरकार से मृतक के बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने और पत्नी को सरकारी नौकरी देने की भी मांग की है।

कांकेर की घटना के विरोध में छत्तीसगढ़ बंद, कई शहरों में बाजार और स्कूल रहे बंद

रायपुर। कांकेर जिले के अमाबेड़ा क्षेत्र में हुई हिंसा और कथित धर्म परिवर्तन के मामले के विरोध में विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा आज छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया है। बंद का असर राज्य के कई हिस्सों में सुबह से ही देखने को मिल रहा है।

राजधानी रायपुर सहित दुर्ग, जगदलपुर, अंबिकापुर और बिलासपुर में स्कूल, दुकानें और अधिकांश व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद हैं। रायपुर में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफकॉमर्स के सदस्यों के साथ मिलकर बंद को सफल बनाने में जुटे हुए हैं और स्कूलों से अपनी दुकानें बंद रखने की अपील कर रहे हैं। जगदलपुर, अंबिकापुर, दुर्ग और बिलासपुर में भी बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। अधिकांश निजी संस्थान और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हैं, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है।

इस बंद छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफकॉमर्स सहित राज्य के कई व्यापारिक, सामाजिक और धार्मिक संगठनों का समर्थन प्राप्त है। हालांकि, आवश्यक सेवाओं को बंद से अलग रखा गया है। अस्पताल, मेडिकल स्टोर और अन्य आपातकालीन सेवाएं सामान्य रूप से संचालित हो रही हैं।

सारांगढ़ में जिला स्तरीय सांसद खेल महोत्सव 2025 संपन्न

सारांगढ़-बिलाईगढ़। सारांगढ़ को खेलभांडा मैदान में जिला स्तरीय सांसद खेल महोत्सव 2025 को आयोजन किया गया, जिसमें अतिथि के रूप में कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे, सांसद प्रतिनिधि अरूण गुड्डू यादव, सत्ताधारी दल के जिला अध्यक्ष ज्योति पटेल, जगन्नाथ केशरवानी, भुवन मिश्रा, दुर्गा प्रसाद ठाकुर, संदीप शर्मा उपस्थित थे। अतिथियों ने सभी खिलाड़ियों और व्यायाम शिक्षक ममता साहू, पूजा अकेला, श्रुति चौबे से पॉक में क्रमवार परिचय लेकर खेल का शुभारंभ किया। खेल की शुरुआत रस्साकसी से हुआ, जो बेहद खुशनुमा और टीम की जोर लगाकर अममाइश करने के लिए उत्साहवर्धक था। इसके बाद 100 मीटर, 200 मीटर दौड़, गेडी दौड़, फुाड़ी, बैडमिंटन, कबड्डी, खोखो, बॉलीबॉल का आयोजन किया गया। जिला पंचायत सांसदों इंद्रजीत बर्मन, एसडीएम वर्षा बंसल, प्रभारी खेल अधिकारी सह डिप्टी कलेक्टर शिक्षा शर्मा, सहायक आयुक्त आदिम जाति विकास विभाग ब्रद्रीश सुखदेवे, उप संचालक समाज कल्याण विभाग, आत्मनिर्भर और टीम का विकास, सुरेन्द्र पैकरा, अखिलेश मिश्रा, राजाराम उरांव, शिव बघेल, दिनेश पटेल, यशवंत और संगीता यादव आदि उपस्थित थे।

राजनैतिक दलों की उपस्थिति में कलेक्टर ने फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियां का किया प्रारंभिक प्रकाशन

कोरबा। भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटीसिव रिवीजन-एसआईआर) कार्यक्रम अंतर्गत अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुणाल दुदावत द्वारा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रारूप मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन राजनीतिक दलों की उपस्थिति में की गई।

उन्होंने उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। कलेक्टर श्री दुदावत ने बताया कि आज मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया गया है। प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के पश्चात 23 दिसम्बर से 22 जनवरी 2026 तक दावा एवं आपत्तियाँ प्राप्त की जाएंगी। प्राप्त दावा-आपत्तियों का निराकरण 23 दिसम्बर 2025 से 14 फरवरी 2026 तक किया जाएगा। सभी प्रक्रियाओं के पूर्ण होने के उपरंत मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 21 फरवरी 2026 को किया जाएगा। कलेक्टर श्री दुदावत ने राजनैतिक दलो के प्रतिनिधियों को प्रारूप निर्वाचक नामावली का प्रतियों सौंपते हुए बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 326 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 16 एवं 19 के अंतर्गत सभी योग्य व्यक्तियों का निर्वाचक सूची में पंजीकरण सुनिश्चित करना है। इसका प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि कोई भी योग्य नागरिक निर्वाचक सूची में शामिल होने से वंचित न रह जाए तथा कोई भी अयोग्य व्यक्ति का नाम सूची में सम्मिलित न होने पाए। संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार, किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में पंजीकरण तभी संभव है।



सुशासन समाह के अंतर्गत मचान्दुर में जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर संपन्न

प्रशासन पहुंचा गांव में, जनता से प्राप्त 210 आवेदनों में से 102 आवेदनों का मौके पर किया गया निराकरण

पावरग्रिड प्रभावित किसानों को मिला मुआवजा राशि

दुर्ग। भारत सरकार के सुशासन ससाह (गुडगवर्नेंस वीक) के अवसर पर जिले में प्रशासन गांव की ओर के तहत बुधवार 24 दिसम्बर को दुर्ग विकासखण्ड के गांव मचान्दुर में जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस शिविर में प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, दुर्ग ग्रामीण विधायक श्री ललित चन्द्राकर भी शामिल हुए। शिविर में विभिन्न विभागों के जिला प्रमुख अधिकारियों द्वारा विभाग से संबंधित आम जनता की समस्याओं का मौके पर निराकरण किया गया। इस दौरान

विभागों को प्राप्त कुल 210 आवेदनों में से 102 का मौके पर निराकरण किया गया। शेष आवेदनों के निराकरण हेतु एक सप्ताह की समय निर्धारित की गई है। समाज कल्याण विभाग द्वारा ग्राम बोरीगारका निवासी श्री बिसाहू राम गजपाल को उनके आवेदन पर त्वरित कार्यवाही करते हुए विभाग की ओर से व्हीलचेयर उपलब्ध कराया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 03 नवनिहालों का अन्नप्रासन्न संस्कार तथा 03 नवविवाहिता महिलाओं की गोदभराई रस्म की अदायगी की गई। बीज प्रक्रिया केन्द्र द्वारा आरबीकेवाय रण्णार योजना अंतर्गत क्षेत्र के 05 कृषकों को रागी किस्म बीएल-376 की मिनी किट वितरण किया गया। राजस्व विभाग द्वारा 400 केवी पावरग्रिड प्रभावित किसान क्रमशः श्री मोहन लाल, श्री जयराम, श्री हरिराम, श्री बिसेलाल, श्री शिवनंदन एवं श्री होमलाल को मुआवजा राशि का चेक वितरण किया गया। ग्राम के आंगनबाड़ी केन्द्र क्रमांक 01,02,03



के सहायिका एवं स्वच्छाग्राही दीदियों क्रमशः श्रीमती हितेश्वरी, श्रीमती रिटावन, श्रीमती कौशिल एवं श्रीमती झरयारिन बाई को विशिष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। इसी प्रकार जल संरक्षण पर आधारित पेंटिंग प्रतियोगिता के प्रतिभागी विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। शिविर में अधिकारियों ने विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से ग्रामीणजनों को अवगत कराया। विधायक श्री चन्द्राकर ने अपने कर-कमलों से विभिन्न योजनाओं के

हितग्राहियों को सामग्री वितरण किया एवं विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया। उन्होंने शिविर स्थल पर जिला पंचायत द्वारा जल संरक्षण हेतु बनाये गये प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने समस्त विभागीय स्टॉलों में भ्रमण कर अधिकारियों से जनता से प्राप्त आवेदनों के निराकरण के संबंध में विचार व्यक्त करते हुए विधायक श्री ललित चन्द्राकर ने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप एक

निश्चित अंतराल पश्चात् जिला प्रशासन द्वारा जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित किया जा रहा है। शिविर के माध्यम से शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से जनता को जुड़ने का अच्छा अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि पात्र हितग्राहियों को शासन की योजना से लाभान्वित करना शिविर का उद्देश्य रहा है। विधायक श्री चन्द्राकर ने बताया कि आज पात्र हितग्राहियों को डीबीटी के माध्यम से अनुदान राशि मिल रही है। डीबीटी की देन प्रधानमंत्री जी की सोच है। उन्होंने केन्द्र सरकार की जन-धन खाता, पीएम आवास, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान चिकित्सा सुविधा को विस्तारपूर्वक रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ समर्थन मूल्य में किसानों का धान खरीदने वाला पहला राज्य है। प्रदेश सरकार ने भूमिहीन खेतिहर कृषकों के लिए 10 हजार रूपए अनुदान राशि और वेंडरों को बिना ब्याज के व्यापार सुविधा उपलब्ध करायी है। महिला सशक्तिकरण के

लिए महतारी वंदन योजना के साथ सरकार समाज के हर वर्ग के हित में कार्य कर रही है। केन्द्र सरकार के वोक्ल फॉर लोकल की तर्ज पर स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देने का काम कर रही है। विधायक श्री चन्द्राकर ने प्रधानमंत्री जी के विकासोन्मुख भारत की परिकल्पना को साकार करने, प्रदेश को भी विकसित बनाने में आम जनता से सहयोग की अपेक्षा की। कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने अवगत कराया कि प्रशासन गांव की ओर अभियान विगत 19 तारीख से लगातार जारी है। जिसके अंतर्गत अनपढ़ एवं नगरीय निकाय क्षेत्रों में शिविर आयोजित किय जा रहे हैं और आज यहां पर जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किये गया है। जिसमें विभागीय अधिकारियों द्वारा आम जनता की समस्याओं का समाधान किया गया है। उन्होंने कहा कि उपलब्ध संसाधनों का अधिक से अधिक संचय किया जाए।

संक्षिप्त-खबर

कलेक्टर श्री सिंह ने धान उपार्जन केन्द्र मचान्दुर का किया निरीक्षण



दुर्ग। कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने बुधवार 24 दिसम्बर को धान उपार्जन केन्द्र मचान्दुर का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने यहां पर धान के स्टेग, प्रत्येक स्टेग में बोरो की संख्या, अब तक खरीदे गये धान और उठाव के साथ ही किसानों की टोकन व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने वाहन एन्ट्री पंजी एवं अन्य पंजी संधारण सही नहीं पाये जाने पर समिति प्रबंधक को फटकार लगायी। साथ ही धान पंजीयनों का व्यवस्थित ढंग से संधारण करने के कड़े निर्देश दिये। इस अवसर पर एसडीएम श्री हरवंश सिंह मिरी और तहसीलदार श्रीमती काश्मा यदु भी मौजूद थे। ज्ञात हो कि उपार्जन केन्द्र मचान्दुर में 29।139.60 क्विंटल धान की खरीदी हुई। जिसमें मोटा धान की मात्रा 15061.60 क्विंटल, पतला धान की मात्रा 2055.20 क्विंटल एवं सरोना धान की मात्रा 12322.80 क्विंटल शामिल है। खरीदे गये धान की कुल लागत राशि 6 करोड़ 90 लाख 72 हजार 816 रूपए है। जिसमें किसानों की 4 करोड़ 70 लाख 9 हजार 595 रूपए का भुगतान किया जा चुका है। धान खरीदी से 617 किसानों को लाभान्वित किया गया है। उपार्जन केन्द्र में खरीदे गये धान का उठाव भी किया जा रहा है। अब तक मिलर्स द्वारा 11 हजार क्विंटल का धान उठाव किया जा चुका है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद हेतु आवेदन आमंत्रित

दुर्ग। एकीकृत बाल विकास परियोजना जामगांव-एम. (पाटन-02) दुर्ग के अंतर्गत परिक्षेत्र सिकोला के आंगनबाड़ी केन्द्र आगोण्ड्री के रिक कार्यकर्ता पद हेतु नियुक्ति किया जाना है। भर्ती की पूर्ण शर्तें एवं आवेदन अवलोकन हेतु परियोजना कार्यालय जामगांव एम एवं कार्यालय जनपद पंचायत पाटन में चस्पा किया गया है। पात्र इच्छुक आवेदिका 7 जनवरी 2026 शाम 5.30 बजे तक बंद लिफफ (डाकघर से) या स्वयं उपस्थित होकर कार्यालय परियोजना अधिकारी एटकीन से मिलकर अभियान चलाकर झोपड़ी की आगजनी से फैल रही आग को तुरंत नियंत्रित कर लिया.

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 2025-26 के लिए ऑनलाइन पंजीयन की तिथि बढ़ी

दुर्ग। जिले में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) सत्र 2025-26 के लिए ऑनलाइन पंजीयन की तिथि बढ़कर 15 जनवरी 2026 हो गई है। पात्र विद्यार्थी पोर्टल के माध्यम से नवीन अथवा नवीनीकरण आवेदन कर सकते हैं। संस्था द्वारा प्रस्ताव लॉक कर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को प्रेषित करने की अंतिम तिथि 5 फरवरी 2026 तक निर्धारित की गई है। वहीं जिला कार्यालय स्तर पर सेक्शन लॉक, भुगतान प्रस्ताव भेजने की अंतिम तिथियां फरवरी 2025 तक निर्धारित हैं। निर्धारित तिथि के बाद पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। समय पर प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने पर छात्रवृत्ति से वंचित होने की जिम्मेदारी संस्था प्रमुख की होगी।

सुशासन के अटल पथ पर अग्रसर छत्तीसगढ़, सुशासन का अटल संकल्प हो रहा साकार

रायपुर। भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति में विकास और सुशासन के प्रतीक हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत विकास की जिस यात्रा की ओर अग्रसर है, उसके पीछे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा दिया गया सुशासन का वह मंत्र पाथेय है, जिसे केन्द्र एवं राज्य की डबल इंजन की सरकारों ने अत्योद्यक की रीति-नीति बनाया है। भारतीय राजनीति के अजातशत्रु कवि हृदय अटल जी छत्तीसगढ़ से गहरा नाता था। छत्तीसगढ़ निर्माण से पहले रायपुर के सप्रे मैदान में आयोजित चुनावी सभा का दृश्य आज भी मुझे याद है, जब अटल जी की एक झलक पाने के लिए छत्तीसगढ़ के कोने-कोने से लोग वहां पहुंचे थे। उस समय उन्होंने जैसे ही छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया का उद्घोष लगाया पूरा मैदान छत्तीसगढ़ महतारी के प्रति आस्था के भाव से स्पंदित हो उठा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आप 11 सीट जीतकर दीजिए, मैं छत्तीसगढ़ राज्य दूंगा। उस चुनाव में हमारी पार्टी के सात सांसद छत्तीसगढ़ से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। श्रद्धेय अटल जी ने छत्तीसगढ़वासियों से किया गया वादा पूरा कर अपनी संकल्पबद्धता को प्रमाणित कर राजनीतिक प्रतिबद्धता का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। 31 जुलाई 2000 को लोकसभा और 9 अगस्त को राज्यसभा में छत्तीसगढ़ राज्य के प्रस्ताव पर रुजर लगी। चार सितम्बर 2000 को भारत सरकार के माध्यम से प्रकाशन के बाद एक नवम्बर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य देश के 26 वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। सौभाग्य से यह वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना का रजत जयंती वर्ष है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ की तीन करोड़ जनता अपने राज्य निर्माता श्रद्धेय अटल जी के पुण्य कृतित्व के लिए उन्हें अपनी आदरंजलि प्रकट कर रही है। माननीय अटल जी राजनीति की परमार्थ का माध्यम मानते थे। वह समावेशी विकास के अगुवा थे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के जरिए उन्होंने देशभर के गांव को पक्की सड़कों से जोड़ा। आज अटल जी के विजन पर देशभर में 6 लाख किलोमीटर से अधिक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें बन चुकी हैं।

राजनांदगांव। चिखली से खैरागढ़ तक हो रहे सड़क निर्माण कार्य में ग्रामों के भीतर नाली निर्माण नहीं किए जाने से क्षेत्र के ग्रामीणों में भारी असंतोष देखने को मिल रहा है। जनपद क्षेत्र तिलई, पदुमतरा, खपरी, चवेली एवं बोरी सहित अन्य ग्रामों के जनप्रतिनिधियों ने इस गंभीर समस्या को लेकर जिलाधीश जितेन्द्र यादव को ज्ञापन सौंपते हुए सड़क के साथ नाली निर्माण की स्वीकृति की मांग की है।

ज्ञापन में बताया गया कि वर्तमान में जिन गांवों से सड़क गुजर रही है, वहां नाली निर्माण का प्रावधान नहीं किया गया है। इससे भविष्य में बरसात के मौसम में जलभराव, गंदगी और आवागमन में परेशानी की गंभीर समस्या उत्पन्न होगी। ग्रामीणों का कहना है कि बिना नाली के सड़क निर्माण अधूरा और अव्यवहारिक है। जनप्रतिनिधियों ने मांग की



है कि स्थल की वास्तविक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्टीमेंट (प्राकलन) में सुधार कर नाली निर्माण की स्वीकृति दी जाए तथा नाली निर्माण पूर्ण होने के पश्चात ही सड़क निर्माण कार्य कराया जाए। इस संबंध में कलेक्टर द्वारा आश्वासन भी दिए जाने की

जानकारी दी गई है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए ज्ञापन की प्रतिलिपि अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग दुर्ग, मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग दुर्ग एवं प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग नया रायपुर को भी भेजी गई है, ताकि शीघ्र आवश्यक

कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

इस अवसर पर प्रमुख रूप से ललित साहू जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 08, ओमप्रकाश साहू पूर्व जनपद सभापति, हिना साहू सरपंच, ग्राम पंचायत पदुमतरा, जीवन साहू सरपंच, ग्राम पंचायत बोरी, भूपेन्द्र निषाद सरपंच-ग्राम पंचायत खपरीखुर्द, मोहन साहू पूर्व सरपंच-ग्राम पंचायत पदुमतरा, विकी साहू सरपंच प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत तिलई, राकेश साहू, गुलाल साहू घनश्याम साहू, राकेश साहू उपसरपंच खपरीकला, सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द नाली निर्माण को स्वीकृति प्रदान की जाए, जिससे भविष्य में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो और सड़क निर्माण कार्य टिकाऊ एवं उपयोगी सिद्ध हो।

वैटरनरी यूनिवर्सिटी के एलुमनाई मीट में देश-विदेश से जुटे भूतपूर्व छात्र

संस्था और छात्रों को आगे बढ़ाने भूतपूर्व छात्रों ने लिया संकल्प

दुर्ग। दाऊ श्री वासुदेव चन्द्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग में विश्वविद्यालय के भूतपूर्व छात्र-छात्राओं का मिलन समारोह एलुमनाई मीट-2025 एवं स्टूडेंटिंग द प्रोफेशनल्स अलाइन्स अमंग एलुमनाई विषय पर राष्ट्रीय सेमीनार का आयोजन किया गया। यह सेमिनार कुलपति डॉ. आरआरबी सिंह के मार्गदर्शन और अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉ. मंजू राय के दिशा-निर्देश में किया गया। सेमिनार में जम्मू-कश्मीर, पंजाब, उत्तराखण्ड, बिहार, झारखण्ड, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, कर्नाटक,



केरल तथा छत्तीसगढ़ से कुल 400 भूतपूर्व छात्रों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। इसके अलावा कतर, कनाडा व अमेरिका से 05 भूतपूर्व छात्र भी सेमिनार का हिस्सा बने। विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सेमिनार अहिंसा विधायक डोमनलाल कोर्सेवाड़ा, दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर, वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन, अधिष्ठाता डॉ. संजय शाक्य, डॉ. मनोज गेंदले, डॉ.

सुधीर उपरीत, विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. बीपी राठिया अतिथि के रूप में मौजूद रहे। विशेष अतिथिगणों में सीनल सिंह, श्रीमती पायल अग्रवाल, डॉ. केके ध्रुव, ब्रिगेडियर डॉ. अमित रस्तोगी उपस्थित थे। एसएसपी विजय अग्रवाल सेमिनार में विशेष रूप से मौजूद रहे। सभी अतिथियों ने एलुमनाई मीट के आयोजन की सराहना की और उसके महत्व पर प्रकाश डाला। विधायक

डोमनलाल कोर्सेवाड़ा ने कहा कि आज का दिन यादगार बन गया है। ऐसे आयोजन जरूरी हैं। विधायक ललित चन्द्राकर ने कहा कि वर्तमान सरकार राज्य के विकास में आप लोगों को हर तरह से सहयोग करने तैयार है। विधायक रिकेश सेन ने कहा कि यह कार्यक्रम एक उत्सव है। एसएसपी विजय अग्रवाल ने कहा कि पशु चिकित्सक अपना काम बड़ी बखुबी निभा रहे हैं। मूक प्राणी की सेवा करना बड़ा पुण्य का कार्य है।

एलुमनाई मीट में शामिल हुए संस्था के भूतपूर्व छात्र शासन में पशु चिकित्सक के रूप में, सेना में, बैंकिंग में कांपोरेट के क्षेत्र में, पुलिस सेवा में प्रशासनिक अधिकारी एवं व्यवसायी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

धान बिक्री से किसान कामता प्रसाद सोनकर चुकाएंगे कृषि ऋण

24 घंटे ऑनलाइन टोकन व्यवस्था से किसान को मिली बड़ी राहत

दुर्ग। खरीफविपणन वर्ष 2025-26 में किसानों की सुविधा और हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा लागू की गई 'तुंहर टोकन मोबाइल ऐप' आधारित 24 घंटे ऑनलाइन टोकन व्यवस्था जिले में सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है। इस नई व्यवस्था के तहत किसान अब घर बैठे ही कभी भी धान बिक्री के लिए टोकन प्राप्त कर पा रहे हैं। इस प्रणाली ने धान खरीदी प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, समयबद्ध और सुगम बना दिया है। पहले जहां

किसानों को टोकन प्राप्त करने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता था, वहीं अब मोबाइल ऐप के माध्यम से यह कार्य आसानी से हो रहा है। इससे न केवल किसानों का समय बच रहा है, बल्कि संसाधनों की भी बचत हो रही है।

इस व्यवस्था का लाभ आज खुड़मुड़ा निवासी किसान श्री कामता प्रसाद सोनकर को मिला। उन्होंने घुघवा उपार्जन केंद्र में 'तुंहर टोकन ऐप' के माध्यम से धान बिक्री हेतु टोकन लिया, जिसमें 63.20 क्विंटल धान की मात्रा दर्ज थी। केंद्र में उनकी धान की तौल सुचारू रूप से और बिना किसी परेशानी के की गई। जिले के सभी



उपार्जन केंद्रों में मोटा, पतला और सरना किस्म के धान की खरीदी नियमित रूप से जारी है। साथ ही, धान के समर्थन मूल्य की दर सूची भी केंद्रों पर स्पष्ट रूप से चस्पा की गई है, ताकि किसानों को पूरी पारदर्शिता के साथ उनकी उपज का

उचित मूल्य मिल सके। श्री कामता प्रसाद सोनकर ने बताया कि धान बिक्री से प्राप्त राशि से वे अपने कृषि संबंधी ऋण चुका पाएंगे। उन्होंने प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस वर्ष धान खरीदी की प्रक्रिया इतनी सरल बना दी गई है कि किसानों को अब टोकन को लेकर किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है। पूरी जानकारी उन्हें समय पर और पारदर्शिता के साथ मिल रही है। 24 घंटे ऑनलाइन टोकन और सुव्यवस्थित धान खरीदी व्यवस्था ने किसानों के लिए एक नई सुविधा तैयार किया है, जिससे वे अपनी फसल का उचित मूल्य प्राप्त कर पा रहे हैं।

मोदी की गारंटी पूरा कराने 29 से 31 दिसंबर तक तृतीय चरण काम बंद-कलम बंद निश्चित कालीन आंदोलन हेतु अनुविभाग पाटन के अधिकारी/कर्मचारी संध द्वारा सौंपा ज्ञापन

पाटन। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय आन्धान पर मोदी गारंटी अनुसार प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान देय तिथि से मंहगाई भत्ता, जुलाई-2019 से लॉबित डी0ए0एरिसर्स की जी0पी0एएच में समायोजित करने, विभिन्न संवर्गों के कर्मचारियों की वेतन विसंगति दुर करने तथा प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना के आधार पर समस्त सेवालाभ सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर दिनांक 29,30,31



दिसंबर-2025 को तीन दिवसीय निश्चितकालीन शांतिपूर्ण काम बंद-कलम बंद हड़ताल में अनुविभाग पाटन अंतर्गत कार्यरत सभी विभागों के कर्मचारी-अधिकारी शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक शाला दुर्ग(झारुआ देवांगन स्कूल जी0ई0रोड दुर्ग) के सामने हड़ताल पर रहने संबंधी ज्ञापन अनुविभागीय दंडाधिकारी महोदय पाटन को सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने के दौरान छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय

प्रवका ललित बिजौरा,संरक्षक टिकेन्द्र वर्मा, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के जिला मीडिया प्रभारी भानु प्रताप यादव, ब्लाक संयोजक महेन्द्र कुमार साहू,संभागीय महामंत्री चंचल विदेवी, पाटन ब्लाक पेंशनर्स अध्यक्ष हीरासिंह वर्मा, सी0एल0 भूआर्य,योगेश्वर महिपाल, सतीश शर्मा, प्रवीण शर्मा, मोतीलाल मार्कण्डेय, ढालसिंग साहू सहित सभी विगाओं के कर्मचारी/अधिकारीगण उपस्थित थे।